02 - जम्मू-कश्मीर में फिर लागू होगा दरबार मूव

03 - 5 नदियों को जोड़ने,दो प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने



A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024

06 - बुजुर्गों के मानवाधिकारों के लिए राष्ट्रपति की चिंता के अर्थ

07 - सांस्कृतिक सम्मोहन में खींची, दुनिया की योगनियां



भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-103 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)



सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

# राज्यहित और लोकहित की प्रभावी जुगलबंदी

अजय बोकिल

## मोहन सरकार का एक साल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उनकी सरकार का पहला साल जनहितैषी फैसलों और विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने के भगीरथ प्रयासों का साल रहा है। वो प्रयास जिनमे राज्यहित और लोकहित की अनूठी जुगलबंदी है। रीजनल इन्वेस्टर्स समिट जैसी अभिनव पहल करके मोहन यादव ने जता दिया है कि विकास का उनका अपना विजन और रोड मैप है। पिछली सरकारों ने मप्र को जहां छोड़ा था, मोहन यादव सरकार की मेराथन रेस, उसी बिंदु से आगे और ज्यादा स्फूर्ति व ऊर्जा के साथ होने वाली है। उपलब्धियों का यह कैनवास बहुआयामी है, जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तटों तक फैला है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के साथ बदलाव की यह धार सरकार की सोच व अप्रोच में साफ झलकती है। साथ में उम्मीदें भी जगाती है। डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला साल 13 दिसंबर को पूरा हो रहा है।

मोहन यादव सरकार के पहले साल को शिवराज सरकार के 18 साल बनाम यादव सरकार का एक साल के आईने में देखना भूल होगी। क्योंकि बीते एक साल में मध्यप्रदेश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, कार्य संस्कृति और अप्रोच एवं तकाजे न सिर्फ बदले हैं बल्कि इसने जनता की उम्मीदों के फलक को और व्यापक बना दिया है। इस कैनवास पर अगर डॉ. मोहन यादव सरकार का मूल्यांकन करें तो हमे उसे अव्वल नंबर ही देने होंगे। इन बारह महीनों में डॉ. मोहन यादव ने न सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर नई रफ्तार से आगे बढ़ने का स्पष्ट संदेश दिया है बल्कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के कुछ विवादास्पद फैसलों को पलटने का साहस भी दिखाया है। त्वरित निर्णय और जनअपेक्षाओं के अनुरूप काम की दिशा तय करने सफल प्रयास मोहन यादव सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सरकार द्वारा लिए गए तमाम फैसलों का निहितार्थ यही है कि मप्र के विकास की नाव भगवा लहरों पर सवार होकर दृढ़ संकल्पित आगे बढ़ती जाएगी। और वह बढ़ती दिख भी रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि सुशासन की राह में आने वाली सभी चुनौतियां खत्म हो गई हैं, लेकिन एक दिशा साफ नजर आने लगी है।

पहली बार और आलाकमान के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने वाले डॉ. मोहन यादव के समक्ष पहली चुनौती तो यही थी कि वो शिवराज की छाया से बाहर निकल अपनी एक नई और सार्थक छवि तैयार करें। यह तभी संभव था कि जब वो सरकार के वादों और फैसलों के त्वरित अमल की नई इबारत लिखें। अपनी सरकार के पहले ही फैसले में मोहन यादव ने हिंदुत्व एजेंडे पर आगे बढ़ने के साथ साथ नौकरशाही में यह स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की मंशा और जनभावना के अनुरूप काम करेंगे तो ही पद पर टिक पाएंगे। गुना जिले में हुए बस हादसे के मामले में जिम्मेदार शीर्ष से लेकर जिले के अफसरों तक को तुरंत हटाना, इसी संकल्प का पहली मिसाल थी।

बीते एक साल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपलब्धियों का ग्राफ बहुआयामी है। अपने संयत और शांत स्वभाव के बावजूद वो यह संदेश देने में नहीं चूके कि कठोर फैसले करने से उन्हें कोई नहीं डिगा सकता। दूसरा, वो मामले को लटकाने की बजाए तेजी से फैसले लेने में भरोसा करते हैं। मोहन यादव की ये उपलब्धियां राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर हैं। राजनीतिक रूप से उन्होंने अपना वर्चस्व पूरी तरह स्थापित कर लिया है। साथ में यह संदेश भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच और अपेक्षाओं को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं रहेगी। रोजगार को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। हालांकि भ्रष्टाचार रोकने, अपराध नियंत्रण, सरकारी तंत्र में कसावट व मप्र की आर्थिक सेहत को सुदृढ़ बनाने के मोर्चे पर अभी काफी कुछ करना बाकी है।

मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना मप्र की जनता के लिए सुखद आश्चर्य था, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में एंटी इनकम्बेंसी को मात देकर चौथी बार भाजपा की बंपर जीत के बाद उन्हीं की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन पार्टी आलाकमान ने मप्र की बागडोर नए हाथों में देने का मन बना लिया था। इसलिए सीएम पद के तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए सत्ता मोहन यादव के हाथों में कमान सौंपी गई। जहां तक राजनीतिक मोर्चे के बात है तो मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा ने मप्र में पहली लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से दो में भाजपा की सीटें बरकरार रखीं। लेकिन विजयपुर सीट वो कांग्रेस से छीन नहीं सके। प्रशासनिक स्तर पर मोहन यादव का काफी समय अपनी टीम बनाने में गया। बावजूद इसके उन्होंने शिवराज सरकार के कुछ फैसले जन भावना के अनुरूप पलटने में संकोच नहीं किया। जिसमें भोपाल और इंदौर में बीआरटीएस हटाने, भोपाल के विकास के लिए बने राजधानी परियोजना प्रशासन को फिर से जीवित करना तथा लगभग 20 साल पहले बंद किए गए राज्य सड़क परिवहन निगम को पुर्नजीवित करना शामिल है। मोहन यादव के समक्ष बड़ी चुनौती मप्र में विकास की रफ्तार तेज करने, अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा रोजगार जुटाने की रही है। आर्थिक विकास और निवेश की दृष्टि से डॉ.मोहन यादव सरकार ने क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन करके एक नई और अभिनव पहल शुरू की है। इन सम्मेलनों में उद्योगों से बड़े पैमाने पर एमओयू हुए हैं। अगर ये जमीन पर उतरते हैं तो मप्र में रोजगार बड़े पैमाने पर सृजित होंगे। आर्थिकी को नई गति मिलेगी। इसी तरह सीएम ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा की। जिसमें मप्र में 78 हजार करोड़ रू. के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से एक प्रस्तावक को जर्मनी में ही जमीन आवंटन का आदेश जारी कर सीएम यादव ने सकारात्मक संदेश दिया है। इसके अलावा आगामी वर्ष 2025 को प्रदेशभर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने, प्रदेश में पर्याप्त बिजली उत्पादन की दृष्टि से 41 हजार मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन की मंजूरी, पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर हस्ताक्षर, नई शराब नीति तैयार करने, धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ बायपास के लिए 701 करोड़ रू. की मंजूरी, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण, इंदौर-उज्जैन के बीच एक और ग्रीन फील्ड रोड बनाने को स्वीकृति आदि प्रमुख हैं। वैसे भी उज्जैन मोहन यादव का गृहनगर और देश की प्रमुख धार्मिक नगरी होने से उनकी प्राथमिकता में होना स्वाभाविक ही है। सामाजिक स्तर पर उन्होंने स्वयं को बहनो के 'भैया' के रूप में प्रोजेक्ट किया है। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने यह संदेश भी दिया था कि उनकी सरकार हिंदुत्व की राह पर ही चलेगी। इसके अलावा राज्य में गो सरंक्षण तथा सभी जिलों में गीता जयंती मनाने के अहम फैसले भी उन्होंने लिए। इसके अलावा कृष्ण भक्त होने के नाते मोहन यादव ने राम वन गमन पथ की तर्ज पर मप्र में कृष्ण पाथेय स्थल विकास की पहल भी की है।


*लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।*

*संपर्क-*

*9893699939*

ajaybokil@gmail.com


# मंदिर-मस्जिद विवाद पर कोई नया केस, आदेश या सर्वे नहीं

- प्लेसेस ऑफ वर्शिप मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट,केंद्र से मांगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मंदिर-मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाएं अदालतें

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि जब तक इन याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक देश में इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी अब मस्जिदों पर दावे वाले नए केस दाखिल नहीं होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना हलफनामा दाखिल करे। अदालत ने केंद्र को चार सप्ताह में याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने केंद्र द्वारा याचिकाओं पर जवाब दाखिल किए जाने के बाद संबंधित पक्षों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने कार्यवाही में हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाले मुस्लिम निकायों सहित विभिन्न पक्षों की याचिकाएं भी स्वीकार कर ली हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक सर्वेक्षण के लिए कोई नया वाद किसी भी अदालत में दायर या पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अगले आदेश तक लंबित मुकदमों में अदालतें कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी।

# 'एक देश एक चुनाव' पर मोदी कैबिनेट की मुहर

अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है यह बिल,पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देशभर में चुनाव

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** एक देश एक चुनाव को गुरुवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट से पास होने के बाद अब इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।

एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कानून की वकालत करते हुए कहा था कि लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। सूत्रों ने यह दावा करते हुए बताया कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में कैबिनेट ने वन नेशन-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन में जनकल्याण शिविर का शुभारंभ किया

# फ्रीगंज एवं आस-पास के क्षेत्र को प्रमुख व्यापारिक, सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा : मुख्यमंत्री

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए दिन रात कार्यरत है। उज्जैन के लिए होने वाले कार्य, संपूर्ण प्रदेश व देश का मान बढ़ाने वाले काम है। बारह ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग बाबा श्री महाकाल के मंदिर में देश विदेश से आने वाले भक्तों की आने-जाने, रूकने की सुविधा, सिंहस्थ एवं जनता जनार्दन के लिए यह कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष-2024 के सावन माह में देश विदेश से एक करोड़ से अधिक संत-महंत-श्रद्धालुओं ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लिए। उज्जैन में विकास के कार्य इतनी अधिक संख्या में आने वाले श्रध्दालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव उज्जैन में फ्रीगंज रेलवे ओवर ब्रिज के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनकल्याण पर्व में सार्वजनिक कार्यक्रम 11 से 26 दिसम्बर तक होंगे। इसके साथ हर दिन नागरिकों को सौगात व हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में गीता जयंती से 26

जनवरी 2025 तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अब नागरिकों को आयुष्मान कार्ड, संपत्ति कर, बिल्डिंग परमिशन, आधार कार्ड एवं इसके साथ 76 से अधिक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ 'आपकी सरकार आपके द्वार' आकर देगी। पहले 'आपका विधायक-आपके द्वार' से कार्य हमने किया अब 'आपकी सरकार-आपके द्वार' आकर एवं शिविरों के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान' गीता जयंती से शुरू हुआ है। गीता भक्ति,ज्ञान एवं योग का मार्ग प्रशस्त करती है। आज भगवान श्रीराम अयोध्या में विराज कर संपूर्ण विश्व के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार अब रामराज्य की परिकल्पना साकार कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने फ्रीगंज के नए रेलवे ओवरब्रिज के भूमि-पूजन के प्रस्तावित नए रेलवे ओवरब्रिज के ले-आउट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। यह ब्रिज चामुंडा चौराहे से फ्रीगंज को जोड़ेगा। फ्रीगंज रेलवे ओवर ब्रिज उज्जैन की आबादी एवं सिंहस्थ -2028 को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत 91.76 करोड़ रुपए होगी। ब्रिज 21.40 मीटर चौड़ा एवं 633 मीटर लंबा होगा।

## सुप्रभात

बच्चों के होमवर्क में
नहीं होतीं घर की कोई बातें
गुल्ली-डंडा, छुपम-छुपाई,
और दादी नानी की
कहानी भरी रातें
फसलों की महक
तालाब, मेंढक और मछलियां
नीम के पेड़ पर चढ़ता-उतरता
गिलहरियों का झुंड।
तवे पर नाचती गोल रोटी
गाय के गले में पड़ी घंटी की रुनझुन
नरम-नरम घास का एहसास
पत्तों पर दमकती उसकी बूंदें
सुबह की गुनगुनी धूप
और पूनम-अमावस की रातें
हां, बच्चों के होमवर्क में
नहीं होतीं घर की कोई बातें।

**- प्रमोद दीक्षित मलय**

# हाड़ कंपा रही सर्दी, शून्य की ओर बढ़ रहा पारा

- कहीं बर्तनों में जम रहा पानी,तो कहीं घास और पत्तों पर जमी ओस
- राजस्थान के 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश 7 राज्यों में गुरुवार को कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिमाचल में शुक्रवार को 5 जिलों में बर्फबारी के आसार हैं। आज से मौसम साफ रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

दिल्ली के साथ-साथ मुंबई में भी सुबह भारी कोहरा दिखाई दिया। दिल्ली में सुबह एयर क्वालिटी खराब की कैटेगरी में आ गई। नेहरू नगर में एक्यूआई 310 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। 26 जिलों में कोहरा छाया है और विजिबिलिटी घटकर 70 मीटर हो गई है। उधर, तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी है। यहां भारी बारिश के चलते 11 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीत लहर का अलर्ट है। आगे भी राहत की उम्मीद नहीं है। हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान है। पंजाब के 17 जिलों में यलो अलर्ट का अनुमान जाहिर किया है। उत्तरी हवाओं से राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई। हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा सीकर और चूरू रहे।

सभी भारतीयों के लिए खुशखबरी

# भारत के डी गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने

**नईदिल्ली (एजेंसी)।** भारत के डी गुकेश शतरंज ने दुनिया में सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर अपनी बादशाहत साबित की। भारतीय ग्रैंडमास्टर ने चीन के डिंग लिरेन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब अपने नाम किया। गुकेश ने यह जीत काले मोहरों से खेलते हुए दर्ज की। डी गुकेश ने इस जीत के साथ ही विश्वनाथन आनंद के एलीट क्लब में एंट्री मार ली है। वे विश्व चैंपियन बनने वाले भारत के सिर्फ दूसरे शतरंज खिलाड़ी हैं। सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई अभिनंदन...।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 18 °c
न्यूनतम 13°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 13 दिसंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

# सीएम बोले-लाड़ली बहना से बढ़ रहा लोड, सरकार आय बढ़ा रही

## सरकार का एक साल पूरा होने पर गिनाई उपलब्धियां; बोले- 3 लाख जॉब मिलेंगे



**भोपाल (नप्र)।** मोहन सरकार के एक साल पूरा होने पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में गुरुवार को सीएम डॉ मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने की शुरुआत में कहा- आज 7 नगरीय निकायों के पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं इनमें से छह निकायों में जनता ने भाजपा को जिताकर अपना भरोसा कायम रखा है।

**लाड़ली बहना से लोड पड़ रहा, सरकार आय बढ़ा रही :** सीएम ने महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा- देश में महिलाओं को सबसे ज्यादा 35 प्रतिशत आरक्षण मप्र में दे रहे हैं। हम 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपए गैस रिफलिंग के लिए दे रहे हैं।

1 करोड़ 29 लाख लाड़ली बहनों को अब तक 19212 करोड़ रुपए राशि का अंतरण किया है। जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे ये चल नहीं पाएगी। लोड पड़ेगा फाइनेंशियली तकलीफ है। ये हो नहीं पाएगा। ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड़ पड़ रहा है लेकिन लोड़ पड़ने के साथ ही सरकार अपने आय के साधन बढ़ाती जाए। अपने पैरों पर अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए जब आप आय बढ़ाएंगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने लिए आप सक्षम हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है। हमारी सारी जनकल्याणकारी योजनाओं खासकर बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

**अटल जी का जिक्र करके उपलब्धियों की शुरुआत की :** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने नदी जोड़ो की कल्पना की थी। नदी जोड़ो के माध्यम से उनका अपना विराट दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा था कि क्या यह संभव है ? यह तो प्रकृति जन्य है यह कैसे हो सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हमारी दूसरी बैठक ली तो उन्होंने कहा कि यह बहुत उम्दा आइडिया है इस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये मुद्दे बिना बात के राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से उलझते हैं। मैंने उनकी बात को समझते हुए सोचा कि इसमें उलझन और अड़चन क्या है?

### वीडी बोले- ये तुरंत एक्शन लेने वाली सरकार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि, एक साल पहले आज के ही दिन 13 दिसंबर को मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के साथ भाजपा के संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और डबल इंजन की सरकार ने दोगुना काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत एक्शन करने वाली सरकार है। महिला, किसान, गरीब, युवा इन चार वर्गों पर सरकार ने फोकस किया है। पीएम श्री एम्बुलेंस के माध्यम से सरकार ने संवेदनशीलता प्रदर्शित की है। महिलाओं को 35त्न आरक्षण देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया। मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से लोकल उद्योगपतियों को अवसर देने के लिए शुरुआत की गई है। शहरों के समग्र विकास के लिए देश में मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा उसके लिए मेट्रोपोलिटन सिटी डेवलप करने का प्रयास सरकार ने किया है। आने वाले समय में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो अटल जी का सपना है भी जल्द पूरी होने वाली है।

### अटल जी के जन्मदिन पर केन-बेतवा का भूमिपूजन

सीएम ने कहा- केन-बेतवा प्रोजेक्ट में केवल 10 प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लगेगी। बाकी राशि केंद्र सरकार देगी। अटल जी की जयंती को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अटल जी का वह सपना साकार होते दिखेगा जो उन्होंने नदी जोड़ अभियान को लेकर देखा था। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिले हैं। प्रदेश के 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले हैं। कुल मिलाकर 10 लाख हेक्टेयर इलाके में इससे सिंचाई होगी। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम में आने की सूचना दी है। दोपहर 1:00 छतरपुर जिले में इस योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में दो तरह की एयर एंबुलेंस चल रही है। जहां हवाई पट्टी है वहां एयर एंबुलेंस चल रही है और जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी हाल की घटना है पन्ना में एक रिटायर्ड खनिज अधिकारी सुबह घूमने जा रहे थे और पीछे से ट्रक में उन्हें कुचल दिया उनका पैर बुरी तरह पिचक गया उन्हें तुरंत एयर लिफ्ट करके बंसल हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती कराया और उनका पैर भले ही अलग करना पड़ा लेकिन उनकी जान बच गई।

शपथ लेते ही हमने दो मंत्रालय को एक साथ किया स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग-अलग थे। हर जगह यह एक थे। केवल हमारे राज्य में ही स्वास्थ्य मंत्रालय अलग था।

मध्य प्रदेश में 2003-4 के आसपास करीब 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे अब कुछ समय में पूरे मध्य प्रदेश में 51 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। सीएम यादव ने कहा कि, इंदौर मनमाड़ के बीच बनने वाली रेल लाइन के लिए मध्यप्रदेश में रेलवे का काम देखने के लिए अलग से ओएसडी ला रहे हैं। यह 309 किलोमीटर का लगभग 18,036 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस लाइन के बनने से 4 घंटे की बचत होगी। लगभग ढाई सौ किलोमीटर का सफर बचेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर परिसर में जनकल्याण एवं विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर परिसर में जनकल्याण एवं विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया।

## मरीजों की सुविधा और चिकित्सकीय सेवाओं की सहजता को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

### 1350 बिस्तर का होगा एमवाय हॉस्पिटल इंदौर

**भोपाल (नप्र)।** उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने के सतत कार्य किये जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में एमवाय हॉस्पिटल, इंदौर के विस्तार, उन्नयन और नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने के लिये भविष्योनुमुखी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी लाते हुए मरीजों की सुविधा और चिकित्सकीय सेवाओं की सहजता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1350 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक हॉस्पिटल के प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही नर्सिंग हॉस्टल और कैंसर हॉस्पिटल के प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर अग्रेषित करने के लिये निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन उन्नयन कार्यों से इंदौर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता को नए आयाम मिलेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सतना में प्रस्तावित 650 बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और उससे जुड़ी एप्रोच रोड के निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहे उन्नयन कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिये। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, एमडी बीडीसी डॉ. पंकज जैन सहित स्वास्थ्य विभाग, पीआईयू और मध्यप्रदेश भवन निर्माण निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

## संक्षिप्त समाचार

### जम्मू-कश्मीर में फिर लागू होगा दरबार मूव

**श्रीनगर (एजेंसी)।** जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार राज्य की 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को फिर से बहाल करने की तैयारी में है। बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटीज के प्रतिनिधियों के साथ तीन घंटे की बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि दरबार मूव को फिर से शुरू करेंगे। जम्मू का अपना महत्व है और हम इसकी विशिष्टता को कम नहीं होने देंगे। हमने अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू के बीच राजधानी बदलते रहने की 152 साल पुरानी परंपरा 1872 में जम्मू-कश्मीर के डोगरा राजवंश के महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की थी। एलजी मनोज सिन्हा ने जून, 2021 में यह परंपरा खत्म कर दी थी। इस परंपरा के तहत गर्मियों में राजधानी श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू शिफ्ट कर दी जाती थी।



### अमित शाह के दौरे से पहले अबूझमाड़ में 7 नक्सली ढेर

**जगदलपुर (एजेंसी)।** बस्तर में अमित शाह के दौरे से पहले अबूझमाड़ के रेकावाया इलाके में सुरक्षाबलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि की है। अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। चार जिले के एक हजार से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। इनमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिले की डीआरजी, कोबरा और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। बता दें कि, 1 जनवरी से अब तक 215 नक्सली मारे गए हैं। विजय शर्मा ने बयान दिया कि, कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पिछले 5 सालों में जितने नक्सली मारे गए थे।



### अब हर महीने खाते में आएंगे 1000 रुपए

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली में अब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। इसकी घोषणा करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि दिल्ली की हर महिला के खाते में हर महीने हजार हजार रुपए डाले जाएंगे। दिल्ली सरकार की यह योजना आज से ही लागू हो गई है। केजरीवाल ने महिलाओं से यह भी वादा किया है कि अभी 1000 रुपये वाली रकम को चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव को अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। उससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये आएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।



## महाराष्ट्र कैबिनेट के लिए मोदी-शाह से मिले फडणवीस

### मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, 14 दिसंबर को शपथ संभव

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार गठन के 7 दिन बाद आज गुरुवार को मंत्रिमंडल पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मुलाकात की। वे बुधवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। सूत्रों ने दावा किया कि शाह के साथ मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई। मीटिंग में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हुआ। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों की शपथ हो सकती है। डिप्टी सीएम अजित पवार भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। वे भी शाह से मुलाकात करने संसद पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे। मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो चुका है।



## किसान नेता डल्लेवाल की किडनी फेल होने का खतरा

- हालत बिगड़ने के साथ ही किसानों ने सुरक्षा बढ़ाई, बोले-केंद्र सरकार हमला करवा सकती है

**पटियाला (एजेंसी)।** हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरणव्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को 16 दिन बीत चुके हैं। यह उनका 17वां दिन है। ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। उनकी सेहत पर नजर रखने वाले निजी डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया है कि उनका वजन 12 किलो से अधिक कम हो चुका है। उनकी किडनी कभी भी फेल हो सकती है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं. डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा दिनों तक भूखा रहने के कारण उनके लीवर में भी दिक्कतें हो सकती हैं। गुरुवार को भी किसानों ने सरकारी डॉक्टरों की उस टीम को रोक दिया था जो डल्लेवाल का चेकअप करने आई थी।

### हाथरस रेप पीड़ित के परिवार से मिले राहुल गांधी

## 45 मिनट की बातचीत, पीड़िता के पिता ने लिखी थी चिट्ठी

### 4 साल से कैद में, यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया

**हाथरस (एजेंसी)।** कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिले। उन्होंने 45 मिनट तक परिवार से बातचीत की। राहुल ने अचानक दौरे का प्लान बनाया। सुबह 7 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। इसी साल, 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था- 4 साल से कैद में हूं। न कोई रोजगार है। न ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए। हाथरस में 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घरवालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला देशभर में सुर्खियों में रहा। यूपी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- राहुल हताश हैं। हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने की है। मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल यूपी को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। पीड़ित लड़की के भाई ने बताया- एसडीएम हाथरस नीरज शर्मा कल मेरे घर की पैमाइश करने आए थे। अभी तक हमारी दो मांगें पूरी नहीं हुई।



## दुनिया की सबसे छोटी डोनर बनी उत्तराखंड की सरस्वती

- मां-बाप ने दिल पर पत्थर रखकर किया ढाई दिन की बच्ची का देहदान

**देहरादून (एजेंसी)।** उत्तराखंड में ढाई दिन की सरस्वती का नाम दुनिया की सबसे छोटी देहदाता के रूप में दर्ज हो गया है। बच्ची जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित थी और पैदा होने के मात्र ढाई दिन में ही उसकी मौत हो गई। ऐसे में उसके माता-पिता ने बच्ची का देहदान कर एक मिसाल कायम की है। बच्ची का शव म्यूजियम में सुरक्षित तो रखा जाएगा लेकिन अब उसके माता-पिता कभी भी उसे नहीं देख पाएंगे। ढाई दिन की बच्ची सरस्वती के देहदान की खबर सुर्खियों में है। हर कोई इस बच्ची की असमय मौत और देहदान की खबर से हैरान है। उत्तराखंड के इस युवा दंपति ने अपनी बच्ची का देहदान कर एक बड़ी मिसाल पेश की है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित पुरुषोत्तम नगर निवासी 30 वर्षीय राममेहर और उनकी पत्नी मगन देवी ने मेडिकल एजुकेशन के लिए अपनी ढाई दिन की बच्ची का शव दान दिया है। दून मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को बच्ची का शव दान में दिया गया है। डॉक्टर के अनुसार मगन देवी को लेबर पेन की वजह से दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां रविवार 8 दिसंबर को दोपहर के समय सिजेरियन से उन्होंने बच्ची को जन्म दिया। इस दंपति की यह दूसरी औलाद थी। अभी यह दंपति बच्ची के होने की खुशियां मना ही रहा था कि बच्ची को हृदय संबंधी रोग होने की खबर ने उन्हें हिला कर रख दिया। यह बच्ची आईसीयू वार्ड में भर्ती थी लेकिन 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से दंपती सदमे में थे। इसी दौरान राम मेहर ने अपनी बच्ची की मौत की जानकारी अपने पारिवारिक डॉक्टर जितेंद्र सैनी को दी। ढाई दिन की बच्ची के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से मौत होने की बात पर डॉक्टर जितेंद्र सैनी ने बच्ची के शरीर को दान देने की राय दी।



# लालू परिवार में फूट, एकला चलो की राह पर तेजस्वी

## उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, मीसा भारती और तेज प्रताप गायब

**पटना (एजेंसी)।** राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के राजनीतिक आयाम की जब सम्मिलित रूप से चर्चा होती है तो उनकी आलोचना में सबसे ज्यादा कटाक्ष उनके परिवार वालों को ले कर किया जाता रहा है। पर वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद कहीं न कहीं बंटा हुआ दिखता है। यह चाहे चुनावी मंच हो या चुनावी यात्रा। देखा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं। आखिर राजनीति में परिवार की सामूहिकता दिख क्यों नहीं रही है। आइए विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर एक तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही संभाले हुए हैं। काफी अरसे से देखा जा रहा है कि चुनावी मंच पर तेजस्वी यादव अपने सहयोगी या फिर स्थानीय नेताओं के साथ मंच साझा करते रहे हैं। अपने इस मंच पर न तो पाटलिपुत्र लोकसभा से राजद की संसद मीसा भारती, छपरा के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रोहिणी आचार्या या फिर हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ही नजर नहीं आते। अब इसकी वजह क्या है यह तो राजद परिवार जाने मगर लालू यादव का परिवार सामूहिकता के साथ मंच पर उपस्थित नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है और वह भी नकारात्मक सवाल कुछ ज्यादा। मसलन सक्रिय राजनीति से मीसा भारती या फिर तेज प्रताप को कहीं अलग तो नहीं रखा जा रहा है या कि परिवारवाद के भीतर कहीं कोल्ड वार तो नहीं छिड़ा हुआ है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पारिवारिक ही नहीं राजनीतिक बॉन्डिंग भी काफी मजबूत दिखता है। प्रियंका की बात करें तो राहुल गांधी के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी या फिर संलिप्तता की बात करें तो वह सौ फीसदी दिखता है। कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' की ही बात करें तो प्रियंका की संलिप्तता साफ दिखती है। गाजियाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। बाद में मीडिया के लिए प्रसारित एक वीडियो में राहुल-प्रियंका मंच पर एक साथ बैठे हैं। इस दौरान राहुल अपनी बहन प्रियंका का माथा चूमा और उनसे बातें करने लगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और पार्टी सांसद राहुल गांधी की लोनी बॉर्डर पर प्रशंसा करते कहा भी कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती क्योंकि उन्होंने सच्चाई की ढाल ओढ़ रखी है, मेरे भाई को कभी नहीं खरीद सकते क्योंकि वह सच्चाई के लिए खड़े हैं।

# 5 नदियों को जोड़ने,दो प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने

## एमपी में बुंदेलखंड और चंबल से मालवा तक पानी मिलेगा; 22 जिले कवर होंगे

**भोपाल (नप्र)।** नदियों को जोड़ने वाले दो बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड में केन और बेतवा को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एमपी में बुंदेलखंड हिस्से के 10 जिलों को पानी मिलेगा।

दूसरा पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक प्रोजेक्ट है। इन तीन नदियों को जोड़ने से एमपी के चंबल से लेकर मालवा तक फायदा होगा। पीकेसी प्रोजेक्ट से प्रदेश के 12 जिलों में सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। दोनों ही प्रोजेक्ट का भूमिपूजन इसी महीने होने की संभावना है।

पीकेसी परियोजना का भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को जयपुर से करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव, दोनों राज्यों के जल संसाधन विभागों के मंत्री, केंद्र और राज्य सरकारों के अफसर मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं की खास बात यह है कि केन-बेतवा लिंक देश का इस तरह का पहला तो पीकेसी दूसरा प्रोजेक्ट है।

### पहले बात केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की

**22 साल बाद पूरा होगा पूर्व पीएम वाजपेयी का सपना-** केन और बेतवा बुंदेलखंड की दो सबसे बड़ी नदियां हैं। दोनों अलग-अलग छोरों पर बहती हैं। यमुना की इन दो सहायक नदियों को एक लिंक कैनाल से जोड़ने की योजना है। बुंदेलखंड लगभग 23733 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। केन और बेतवा नदी यहां की लाइफलाइन हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में जल संकट बड़ी चुनौती है। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़कर बर्बाद होते पानी को रोकने के प्रयास शुरू किए थे। 2003 में एमपी की तत्कालीन सीएम उमा भारती ने भी इस परियोजना को अमल में लाने का प्रयास किया था। अब 22 साल बाद पूर्व पीएम वाजपेयी का सपना साकार होने जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस परियोजना के भूमिपूजन के लिए समय मांगा है। अगर मंजूरी मिली तो 25 दिसंबर से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। छतरपुर जिले में दौधन बांध पर निर्माण का भूमिपूजन किया जाएगा।

**कहां से कहां जुड़ेंगी केन और बेतवा नदियां-** छतरपुर और पन्ना जिले के बॉर्डर पर खजुराहो के करीब केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा। इस बांध से 230 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए केन नदी का पानी निवाड़ी और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बॉर्डर पर ओरछा के करीब बेतवा नदी में जोड़ा जाएगा।

# मासूम बेटी पर छुरी से हमला, तीन अंगुलियां कटीं

## भोपाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, 12 घंटे बाद घर छोड़ा; थोड़ी देर बाद मौत

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में युवक ने 6 साल की बेटी पर छुरी से हमला कर दिया। मासूम ने बचाव में अपना हाथ आगे किया। इससे उसकी 3 अंगुलियां कट गईं। उसके सिर और गले में भी चोट आई है। बच्ची को बचाने आए अपने बड़े भाई को भी आरोपी ने छुरी मारकर घायल कर दिया। दोनों हमीदिया में भर्ती हैं।

घटना मंगलवार - बुधवार की दरमियानी रात शहर के छोला मंदिर इलाके की है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। 12

घंटे बाद जमानत मिलने पर बुधवार शाम उसे घर भी छोड़ गई, इसके थोड़ी देर बाद युवक की मौत हो गई। गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजने के हवाले कर दिया। दो पुलिसकर्मी घर तक छोड़कर आए थे।

केंची छोला का रहने वाला कमल रायकवार (28) पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। उसके छोटे भाई सोनू रायकवार ने बताया कि भाभी (कमल की पत्नी) ने 5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। उनकी बेटी इशिका (6) प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती है। भाई शराब पीने का आदी था। नशे में बेटी पर छुरी से हमला किया। बड़े भाई मुकेश ने बीचबचाव किया, तो उन्हें भी छुरी मार दी। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। भाई की शिकायत पर उसके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। 12 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। आरोपी को प्रधान आरक्षक प्रहलाद और आरक्षक आशीषघार तक छोड़कर आए। पुलिस के लौटते ही युवक की मौत हो गई।

**थाना प्रभारी बोले- युवक का लिवर खराब था-** युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर छोला थाने के प्रभारी सुरेशचंद्र नागर का कहना है, युवक की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिल गई है। लिवर खराब होने की वजह से मौत होने की बात इसमें लिखी है। दोनों पुलिसकर्मी उसे छोड़कर रवाना हो गए थे। इसके बाद कमल की मौत हुई है।

# रजिस्ट्रार का एबीवीपी के कार्यक्रम में जाने पर विवाद

## एनएसयूआई के विरोध के बाद अब दिग्विजय ने किया ट्वीट, सीएम से पूछा सवाल

**भोपाल (नप्र)।** माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में कुलसचिव अविनाश बाजपेई और कुलपति पद के आवेदक डॉ. आशीष जोशी और प्रोडक्शन सहायक डॉ. परेश उपाध्याय की नेम प्लेट पर काला रंग लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया हैं।

इसके अलावा जगह-जगह आरएसएस ऑफिस और एबीवीपी भी

लिखा, इस मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया हैं। उन्होंने एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा क्या एवीबीपी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में जो सभी को समान अधिकार देने का पैरामेवेल में प्रावधान है उसका समर्थन करती है? यदि हाँ तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ नफ़रत फैलाना बंद करें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के अनुसार, उन्होंने भाजपा और संघ समर्थित शिक्षा के राजनीतिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया हैं। कार्यकर्ताओं ने कुलसचिव डॉ. अविनाश बाजपेई और कुलपति पद के आवेदक डॉ. आशीष जोशी और प्रोडक्शन सहायक डॉ. परेश उपाध्याय की नेम प्लेट पर काला रंग लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा जगह-जगह आरएसएस ऑफिस एबीवीपी भी लिखा।

# श्री महाकाल के बनने से श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई

- **मुख्यमंत्री डॉ.यादव के नेतृत्व में श्रावण-भादौ मास में अवंतिका नगरी में बना डमरूवादन का विश्व रिकॉर्ड**

**भोपाल (नप्र)।** उज्जयिनी एक महान धार्मिक सांस्कृतिक, साहित्यिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक सिद्ध नगरी है। पृथ्वी के नाभिस्थल पर स्थित होने से कुण्डलिनी शक्ति-जागरण के सुविज्ञ योगियों एवं आध्यात्मविदों के लिए यह सफलदायी महत्ती सिद्ध भूमि है। यहां पर प्रत्येक 12वें वर्ष में सिंह राशि में गुरू के स्थित होने पर कुम्भ महापर्व का आयोजन सुदीर्घकाल से होता आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और निरंतर विकास के कार्य कर रहे हैं। उज्जयिनी नगरी का विश्व प्रसिद्ध बारह ज्योर्तिलिंगों में से एक दक्षिणमुखी श्री भगवान महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन की जीवन शैली का केन्द्र बिन्दू है। अवंतिकानाथ भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल महालोक बनने के बाद से देश-विदेश से श्रद्धालुओं का अधिकाधिक संख्या में आगमन हो रहा है और निरंतर श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव की मंशानुरूप भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण-भादौ मास की सवारियों व राजसी सवारी ने सम्पूर्ण भारतवर्ष का ध्यान आकर्षित किया। भगवान श्री महाकालेश्वर का राजसी वैभव व ठाट-बाट देखने देश-विदेश से 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु सिर्फ श्रावण के एक माह में पधारें। मुख्यमंत्री डॉ.यादव के निर्देशानुसार इस वर्ष सवारी में आकर्षण का केन्द्र देश की विभिन्न जनजातिय दलों के कलाकारों द्वारा लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां, पुलिस बैंड द्वारा मधुर धुन की सवारी मार्ग में प्रस्तुति, डमरूवादन का विश्व रिकॉर्ड व राजसी सवारी में भगवान श्री महाकालेश्वर की पालकी रामघाट पहुंचने पर हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा रही।

# एमपी के 33 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

## इंदौर-राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट; भोपाल में कोल्ड डे, स्कूल की टाइमिंग बदली

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश में 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को प्रदेश के 33 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीत लहर चल रही थी भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में कोल्ड डे यानी दिन भी ठंडा रहेगा। बढ़ती ठंड के चलते भोपाल और इंदौर में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। 8वीं तक क्लासेस 9 बजे से लगेंगी।

मौसम विभाग ने गुरुवार को इंदौर और राजगढ़ में कोल्ड डे और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, निवाड़ी, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और उमरिया में कोल्ड डे रहेगा। वहीं, धार, बड़वानी, खंडवा, नर्मदापुरम, आगर-मालवा, गुना, सागर, शहडोल, जबलपुर और सिवनी में सर्द हवाएं चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग, भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि उत्तर भारत में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। इस वजह से ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

### ठंड बढ़ने के ये 2 कारण

पश्चिम-उत्तर भारत में 12.6 किमी की ऊंचाई पर 278 किमी प्रतिघंटा की गति से जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव है। इस वजह से बर्फ पिघल रही है। जिससे हवा में ठंडक है।

रायसेन में रात का पारा 4.4 रिकॉर्ड किया गया। यहां गुरुवार सुबह ओस की बूंदें पत्तियों पर जम गईं।

### पचमढ़ी सबसे ठंडा, भोपाल-ग्वालियर में भी लुढ़का पारा

बुधवार-गुरुवार की रात पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, बीती रात की तुलना में तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

ग्वालियर में पारा 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, भोपाल में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 10 डिग्री, उज्जैन में 8.5 डिग्री और जबलपुर में 6.2 डिग्री रहा। पचमढ़ी के अलावा नौगांव, रायसेन, राजगढ़, उमरिया ऐसे शहर रहे, जहां पारा 5 डिग्री के नीचे रहा।

### इस बार पहले पखवाड़े में ही कड़ाके की ठंड

इस साल दिसंबर की सर्दी ने ट्रेंड बदल दिया है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड और ट्रेंड देखें तो दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की ठंड पड़ती रही है लेकिन इस बार पहले ही पखवाड़े में तेज सर्दी का असर है। भोपाल और इंदौर की रात तो पिछले 2 साल में सबसे ठंडी रही हैं यानी दिसंबर की ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी पारा सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे रहा। अब दिसंबर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

# जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लड नहीं मिला, मरीज की मौत

## स्टाफ ने बाहर किया, बेटा ठंड में शव लेकर बैठा रहा; अधीक्षक बोले- जानकारी नहीं

**जबलपुर (नप्र)।** जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लड नहीं मिलने पर मरीज ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने शव को बाहर रख दिया। 16 साल का बेटा कड़ाके की ठंड में पिता के शव को लेकर पेड़ के नीचे बैठा रहा।

रात में गश्त के दौरान गढ़ा पुलिस थाना के स्टाफ की नजर लड़के पर पड़ी। जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की और शव को लेकर लड़के के गांव छोड़कर आई। जब मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा - मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ब्लड न मिल पाने के कारण किसी मरीज की मौत हो गई। इस विषय में ड्यूटी डॉक्टर ही जानकारी दे सकेंगे। यह भी हो सकता है किसी और कारण से मरीज की मौत हुई है। जानकारी ली जा रही है।

**16 साल के बेटे से खून का इंतजाम करने को कहा-** करेली के ग्राम गढ़ाई में रहने वाले नर्मदा प्रसाद सिलावट को दो दिन पहले नरसिंहपुर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। नर्मदा प्रसाद के बेटे नारायण ने बताया, पिता को खाने-पीने में तकलीफ हो रही थी। मेडिकल कॉलेज आने के बाद काफी आराम भी मिला, लेकिन बुधवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से खून का इंतजाम करो। 16 साल का बेटा पिता के लिए खून का इंतजाम करता रहा, लेकिन ब्लड नहीं मिल पाया। पिता की मौत के बाद स्टाफ ने रात करीब 11 बजे शव को मेडिकल कॉलेज के बाहर रख दिया। बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पिता के शव को गांव तक ले जा सके। वह शव के पास ही बैठ गया। पुलिस टीम ने पहुंच कर शव को वापस स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस का इंतजार करता स्टाफ।

**पुलिस ने खाना खिलाया, एम्बुलेंस बुलाई-** रात करीब 2.30 बजे गढ़ा थाना पुलिस गश्त करते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे लड़के पर पड़ी।

पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इलाज के दौरान बड़े भाई-भाभी और चाचा थे। जैसे ही पिता की मौत हुई बिना बताए चले गए। पुलिस ने पहले लड़के को खाना खिलाया। फिर तड़के 3 बजे शव के साथ करेली रवाना करवाया।

### लड़के को देखा तो स्टाफ को सूचना दी

गढ़ा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी अनिल यादव ने बताया, रात को गश्त के दौरान मेडिकल कॉलेज के बाहर लड़का बैठा था। उसके पास पैसे नहीं थे। हमने अपने स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद और भी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की व्यवस्था की।

### इंदौर में होगा प्लास्टपैक 2025

# 400 से अधिक कंपनियों के 2 हजार एग्जिबिटर्स का लगेगा मेला

**भोपाल (नप्र)।** प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन 'प्लास्टपैक 2025' आयोजन लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर इंदौर में 9 से 12 जनवरी, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम 'प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, पाइप, एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी' है।

प्लास्टपैक 2025 में देशभर के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईपीपीएफ की टीम देश भर के मुख्य शहरों में पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में 12 दिसम्बर को प्लास्टपैक की टीम भोपाल पहुंची और मीडिया से मुलाकात की, जिसमें प्लास्टपैक के दो दिवसीय आयोजनों की रूपरेखा साझा की गई।

इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोग इस चार दिवसीय आयोजन में शामिल होने की उम्मीद हैं। इसमें मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्लास्टिक उद्योगपति शामिल होंगे। इस आयोजन में प्रवेश निःशुल्क है। प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा, मेडिकल, फूड, फर्नीचर इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगपति, प्रोफेशनल्स के साथ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र इस आयोजन में शामिल होंगे।

**400 से अधिक कंपनी होगी शामिल-** इंडियन प्लास्टपैक फोरम अंकित भारुका ने बताया कि 400 से अधिक कंपनियों के 2000 से अधिक एग्जिबिटर्स इस आयोजन में भाग लेंगे। प्लास्टपैक 2025 के लिए संपूर्ण लाभ गंगा एग्जिबिशन सेंटर को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख कंपनियों के स्टॉल पर लाइव मशीनों और उत्पाद का प्रदर्शन होगा।

### विरासत से विकास बाइक रैली को रवाना करेंगे सीएम

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा 13 दिसम्बर को होंगे बाइक रैली में शामिल। गोल जोड़ चौराहा कोलार रोड से सुबह 10 बजे बाइक रैली को करेंगे रवाना।

# गैंगरेप, पॉक्सो में केस दर्ज

- **वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, रिश्तेदार को दिखाया, तीन आरोपी गिरफ्तार**

**सीहोर (नप्र)।** सीहोर नगर के कस्बा क्षेत्र में गैंगरेप और रेप का वीडियो बनाकर वायरल कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार नगर के कस्बा क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की कक्षा ग्यारह की छात्र है। छात्रा ने कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 2 नवंबर को उसके साथ तीन लोगों ने बलात्कार किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।

**वीडियो बनाकर रिश्तेदार को दिखाया-** तीन लड़कों ने वीडियो बनाकर नाबालिग लड़की के रिश्तेदार को भी वीडियो दिखाया। जिसके बाद लड़की काफी डरी और सहमी रही और उसने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। मामले में पीड़ित लड़की ने इस संबंध में कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया है। थाना प्रभारी मनोज मालवीय ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 61 और 65 दर्ज की गई है तथा 67 आईटी एक्ट भी लगाया गया है। इतना ही नहीं मामले में पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

### जनसुनवाई में भड़कीं महिला आयोग अध्यक्ष, कहा-

# ऐसा पहली बार हुआ जब आईजी-कमिश्नर नहीं आए; भोपाल कलेक्टर भी जाने लगे

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर महिलाओं से संबंधित मामलों की जनसुनवाई में शामिल हुईं। बैठक में भोपाल कमिश्नर संजीव सिंह, भोपाल आईजी और पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्रा की गैर-मौजूदगी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी प्रोटोकॉल अटैंड कर एक अन्य मीटिंग में बाहर जाना चाह रहे थे। रहाटकर ने कहा कि हमारी किसी भी सुनवाई में आईजी-कमिश्नर मौजूद रहते हैं। यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों अफसर नहीं आए।

बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग 'आपके द्वार' कार्यक्रम कर रहा है। इसके अंतर्गत जनसुनवाई के माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही हैं। जनसुनवाई में महिलाओं के लंबित मामलों के समाधान और उनके मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। महिला आयोग की जनसुनवाई में प्रदेशभर से 30 गंभीर मामलों में सुनवाई की जा रही हैं।

**प्रदेशभर से 30 गंभीर मामलों में सुनवाई-** जनसुनवाई पुराने सचिवालय में दोपहर 1 बजे शुरू हुई। इसमें प्रदेश के 30 गंभीर मामलों पर सुनवाई की जा रही है। साथ ही भोपाल और आस-पास के जिलों से आने वाली 90 से 100 शिकायतें भी सुनी जा रही हैं। बैठक में जिला प्रशासन के साथ पुलिस अफसर मौजूद हैं। इन मामलों में त्वरित निराकरण करना है।

**महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं-** बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि किसी भी स्थिति में महिला के साथ अन्याय नहीं होने देना है। अगर समझौते की स्थिति बने, अगर किसी मामले में शिकायत के बाद समझौते की स्थिति बनती है, अथवा महिला शिकायत से पीछे हट रही है, तो भी पुलिस को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए।

**महिला शिकायत वापस लें तो:** कई बार महिलाओं द्वारा शिकायत के बाद सेटलमेंट होने की बात की जाती है और शिकायत वापस ली जाती है।

मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव द्वारा
₹758 करोड़ के विकास कार्यों का
भूमिपूजन एवं लोकार्पण
पूर्वाह्न 11 बजे | कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल

रातापानी टाइगर रिजर्व का
लोकार्पण
प्रातः 10 बजे | गोल जोड़, भोपाल
13 दिसम्बर, 2024






11 दिसम्बर - 26 दिसम्बर 2024
जनकल्याण पर्व

जनसेवा और मध्यप्रदेश के विकास के लिए
निष्ठा और समर्पण का एक साल


# त्वरित निर्णय बने मिसाल

"मैं प्रदेश के आठ करोड़ नागरिकों का आभारी हूं, जिनके सहयोग से हमारा प्रदेश आज अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प के तहत, प्रदेश 'GYAN' गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के चार मुख्य स्तंभों पर आधारित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ रहा है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

"गरीब, युवा, महिला और किसान, 'विकसित भारत' के लिए हम इन चारों स्तंभों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने में जुटे हैं। देश में सिर्फ चार जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं। मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं।

मेरा मानना है कि मूल आस्था और धर्म को छोड़कर इन चार मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा।"

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

## समृद्ध हो रही संस्कृति

- मकर संक्रांति से गीता जयंती तक पूरे वर्ष के त्योहारों को प्रदेश सरकार ने समाज के साथ मिलकर मनाया।
- विक्रम सांस्कृतिक पर्व का 1 मार्च से 9 अप्रैल, 2024 तक आयोजन। कालजयी महानायकों पर केन्द्रित भारत के पहले संग्रहालय "वीर भारत न्यास" का शिलान्यास।
- विक्रमोत्सव पर विश्व की पहली "विक्रमादित्य वैदिक घड़ी" का शुभारंभ कर प्रदेश ने भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया।
- रक्षाबंधन पर बहनों के सम्मान में पूरे श्रावण माह प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों ने बढ़ाई भाई-बहन के स्नेह की प्रतिष्ठा।
- गुरुजनों के सम्मान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। अब हर वर्ष होगा गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन।
- 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय।
- श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों (सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापाव इंदौर एवं अमझेरा धार) को जोड़ कर श्रीकृष्ण पाथेय का होगा निर्माण। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पाठ्यक्रमों में रामायण और गीता वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल।
- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर मध्यप्रदेश में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन निर्माण का निर्णय।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
- मां क्षिप्रा शुद्धिकरण एवं प्रवाहमान बनाए रखने का संकल्प पूरा करने के लिए ₹ 599 करोड़ की लागत की कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन।

## सुशासन की सरकार

- नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिये साइबर तहसील लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, साइबर तहसील 2.0 प्रारंभ।
- ई-पंजीयन एवं ई-स्टेम्पिंग के माध्यम से संपत्ति रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 शुरू।
- राजस्व महाअभियान के दो चरणों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम और सीमांकन के 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा, राजस्व महाअभियान 3.0 प्रारंभ।
- थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य सम्पन्न।
- हर जिले में होगा पुलिस बैंड।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण एवं युक्तिकरण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित।
- 1972 के नियम को बदलते हुए सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान स्वयं करने का निर्णय।
- सुलभ आवागमन के लिए परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर बने चैक पॉइंट।
- खुले में मांस, मछली की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध।
- भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय।
- लाउड स्पीकर की अनियंत्रित एवं अनियमित आवाज का प्रयोग किया प्रतिबंधित।
- वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य।

D-11119/24

## नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण



- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को सफल बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प पूरा किया।
- जल स्रोतों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभूतपूर्व पहल पर जलगंगा संवर्धन अभियान का आयोजन। पर्यावरण दिवस (5 जून) से गंगा दशहरा (16 जून) तक चला अभियान। ₹ 1384 करोड़ की लागत से 56 हजार से अधिक जल स्रोतों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।
- 18 लाख से अधिक नागरिकों ने की जनभागीदारी।

## अभूतपूर्व गति से औद्योगिक विकास

- वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में किया गया घोषित।
- अब तक सम्पन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम से रु. 2.07 लाख करोड़ एवं मुंबई, बैंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में किये गये रोड-शो कार्यक्रमों में ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में ₹ 20 हजार करोड़ के निवेश और यू.के. और जर्मनी की यात्रा में ₹ 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से कुल ₹ 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
- प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र प्रारंभ किये गए।
- मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना का निर्णय।
- नर्मदापुरम जिले के मुहासा-बाबई इंडस्ट्री एरिया में रिन्युबल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित उपकरणों की इकाइयों का भूमिपूजन।

## आगे बढ़ते युवा

- युवाओं की शिक्षा एवं आधुनिक तकनीकों में योग्यता और कौशल निर्माण के साथ सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवा शक्ति मिशन प्रारंभ।
- सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर की जा रही भर्तियां। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती का लक्ष्य। पदों की भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर होगा जारी।
- भारत सरकार के पीएलएफ सर्वे में मध्यप्रदेश ने दर्ज की सबसे कम बेरोजगारी दर।
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में 20 हजार चयनित युवाओं को लगभग ₹ 41 करोड़ स्टाइपेंड वितरित।
- स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹ 50 हजार से लेकर ₹ 1.50 लाख तक वित्तीय सहायता।
- अग्निवीर योजना में युवाओं का चयन हो, इसके लिए 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य। मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को मिलेगा आरक्षण।
- प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय।
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्गत सभी जिलों में बनेंगे खेल स्टेडियम।।
- भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।
- वर्तमान में कुल 268 शासकीय आई.टी.आई. संचालित। इस वर्ष 22 नये आई.टी.आई. प्रारंभ करने से 5280 अतिरिक्त सीट्स की होगी वृद्धि।

## जनजातीय समाज को समान अधिकार

- छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लायओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाने जायेंगे।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय ₹ 3000 प्रति बोरा से बढ़ाकर किया ₹ 4000।
- पीएम जन-मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में ₹ 7300 करोड़ से अधिक की लागत से हो रहे अधोसंरचना कार्य। 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित।
- पीएम जन-मन योजना अन्तर्गत देश में सर्वप्रथम जन-मन कॉलोनी शिवपुरी में बनाकर मध्यप्रदेश योजना में अग्रणी। देश की सबसे पहली जन-मन सड़क बालाघाट जिले में बनकर तैयार।
- युवाओं को यूपीएससी, पीएससी, सिविल जज, गेट, कैट आदि के लिए निःशुल्क कोचिंग का निर्णय।

## गरीब वर्ग को समान अवसर

- इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को ₹ 224 करोड़ की लंबित राशि का भुगतान।
- संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को ₹ 895 करोड़ से अधिक का अंतरण।
- स्वामित्व योजना में 24 लाख भू-अधिकार पत्र वितरित कर प्रदेश देश में प्रथम।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹ 10 हजार से 50 हजार तक ऋण सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 55 लाख हितग्राहियों को ₹ 3 हजार करोड़ से अधिक राशि का अंतरण।
- 5 करोड़ पात्र हितग्राहियों को 30.59 लाख मी.टन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत वितरित
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों को एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर।

## खुशहाली की ओर अन्नदाता

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को ₹ 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत ₹ 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम ₹ 3900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता।
- वर्ष 2024-25 बजट में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान। लगभग 32 लाख कृषक हो रहे हैं लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-23' में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹ 750 करोड़ से अधिक की राशि के दावों का हुआ भुगतान।
- किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान।
- सोयाबीन का ₹ 4,892 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय।
- 5 वर्षों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन दाल शुरू किए जाने का निर्णय। अरहर, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों के एमएसपी पर उपार्जन की व्यवस्था बनेगी मजबूत।

## आत्मविश्वास से भरपूर नारी शक्ति

- नारी सशक्तिकरण के प्रति सम्मान स्वरूप वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक का जबलपुर में आयोजन।
- मां अहिल्या बाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष एवं विजयादशमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में हुए दशहरा शस्त्र पूजन कार्यक्रम।
- दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय बनाने का निर्णय।
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को मिलेगा अब 35 प्रतिशत आरक्षण।
- लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक ₹ 19 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण।
- प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को ₹ 450 में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में ₹ 715 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख महिलाओं को मिली धुएं से मुक्ति।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना में दिसम्बर 2023 से अब तक 5 लाख 12 हजार बालिकाओं को ₹ 170 करोड़ की छात्रवृत्ति अंतरित।
- स्व-सहायता समूह के अंतर्गत लखपति दीदी योजना से महिलाएं बन रहीं सशक्त और आत्मनिर्भर। 1 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति।
- 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख बहनें हुईं आत्मनिर्भर।
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को ₹ 275 करोड़ का अंतरण।
- सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को ₹ 57 करोड़ 18 लाख की राशि अंतरित।
- जेंडर बजट में ₹ 19 हजार 21 करोड़ से अधिक की वृद्धि। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन के विभागों को ₹ 1 लाख 21 हजार करोड़ का प्रावधान।

## सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

- उज्जैन को मिली मध्यप्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात। मेडिसिटी में सुपरस्पेशिलिटी एवं मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल, चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र जैसी अनेक सुविधाएं होंगी उपलब्ध।
- पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल।
- आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल, ₹ 1381 करोड़ का प्रावधान।
- वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित। 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन एवं पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र प्रारंभ होंगे।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण बना।
- स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों (नियमित/ संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति।
- जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को एक-एक शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय।

## सशक्त भविष्य के लिए शिक्षा

- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ।
- 369 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन, वर्ष 2025 में लगभग 150 नये सीएम राइज विद्यालय होंगे संचालित।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश। नई नीति के तहत वर्ष 2025 से लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में छोटे बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी प्रारंभ होगी।
- ₹ 170 करोड़ से खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन।
- सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ।
- शिक्षा को वैश्विक संस्थानों से जोड़ने के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एम.ओ.यू.।
- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा।

## कायाकल्प की ओर शहरी विकास

- यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।
- प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जायेगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा-राजगढ़ को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।
- भारत सरकार के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी।
- संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्वीकरण तथा पुनर्विकास नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी। जिसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में लाभ से वंचित सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।
- खाली मिलों जैसे हुकुमचंद/विनोद मिल एवं अन्य शहरों में खाली पड़ी शासकीय भूमियों पर शहरी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जायेंगे।
- निर्माणाधीन महाकाल महालोक उज्जैन, संत रविदास लोक सागर, माँ नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, देवी लोक सलकनपुर, श्री रामराजा लोक ओरछा, जाम सांवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, श्री परशुराम लोक जानापाव, महाराणा प्रताप लोक भोपाल, भादवामाता लोक नीमच, माँ पीताम्बरा लोक दतिया और माता मंदिर लोक रतनगढ़ को पूरा किया जायेगा।

## नयी पहचान गढ़ता पर्यटन

- "पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा" का शुभारंभ। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली, उज्जैन एवं खजुराहो के मध्य शुरू हुआ संचालन।
- मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं।
- मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता कॉरिडोर।
- प्राणपुर, सावरवानी एवं लाडपुर खास को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार।

## सेवा और संवर्धन गौ-संरक्षण

- वर्ष 2024 गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक गांव 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
- 10 से ज्यादा गाय पालने पर शासकीय अनुदान देने का निर्णय।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ एमओयू। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करने लगेंगी।
- ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना।
- प्रत्येक 50 किमी पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध। 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ।

## विकास को बल देती अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2024-25 में 16% की बढ़ोतरी के साथ ₹ 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत
- अगले 5 साल में बजट को दोगुना करते हुए ₹ 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य
- आगामी वित्त वर्ष में शून्य बजट का प्रावधान करने का निर्णय।

## प्रगति का आधार अधोसंरचना विकास

### सड़क

- इंदौर में ₹ 350 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर।
- ₹ 10 हजार करोड़ से अधिक की 724 किमी लम्बी विभिन्न 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 3 हजार 500 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए ₹ 5 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति। इसके निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्र मुम्बई-दिल्ली 8 लेन इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर से जुड़ेंगे।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 गांव 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से बारहमासी मार्ग से जुड़े।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 हजार कि.मी. की सड़कों के निर्माण एवं लगभग 2 हजार कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य।
- ₹3589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति।
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत।

### वायुसेवा

- ग्वालियर से बैंगलुरु, अहमदाबाद, ग्वालियर, दिल्ली और अयोध्या के लिए विमान सेवा प्रारंभ।
- विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। रीवा में मध्यप्रदेश का छठवाँ एयरपोर्ट का शुभारंभ।
- ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन।

### रेल

- ₹ 14440 करोड़ की लागत से भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल निर्माणाधीन।
- इंदौर-उज्जैन के मध्य शुरू होगी वन्दे मेट्रो ट्रेन।
- ₹ 18 हजार 36 करोड़ की इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति, 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशनों से जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजनांतर्गत 33 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास एवं 133 रेल ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
- मध्यप्रदेश को 364 विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश को चौथी सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन) ट्रेन मिली।
- भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव और सुविधाओं के विकास हेतु लगभग ₹ 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास।

### नवीकरणीय ऊर्जा

- 12 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन 14 गुना बढ़कर हुआ 7,000 मेगावॉट।
- 308 करोड़ रुपये की लागत से खरगौन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का भूमिपूजन।
- ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से 278 MW विद्युत उत्पादन प्रारंभ।
- इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए हर घर सोलर अभियान का संचालन।
- मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा
- शाजापुर, आगर और नीमच में सोलर पार्क का निर्माण।

### केन-बेतवा लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 दिसम्बर को छतरपुर में परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- परियोजना से प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा
- प्रदेश की कुल 41 लाख आबादी होगी लाभान्वित

### पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 दिसम्बर को परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- प्रदेश के मालवा क्षेत्र के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना में 6.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा।

### अन्य सिंचाई परियोजनाएं

- ₹ 1320 करोड़ की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। सिंगरौली जिले में परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।
- ₹ 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।
- प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित, वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य।

## संपादकीय

# अभिव्यक्ति की आजादी के दोहरे मापदंड

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा एक विशेष कमेटी की सिफारिश पर ब्रिटिश भारतीय समुदाय के दो नेताओं से शाही सम्मान वापस लेने का फैसला यही दर्शाता है कि खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का पहरूआ कहने वाले देश के अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर दोहरे मापदंड हैं। क्योंकि सम्मान वापस लेने के पीछे जो तर्क दिए गए हैं, वो पूर्वाग्रह से प्रेरित ज्यादा लगते हैं। जिन भारतवंशी हस्तियों से ये सम्मान वापस लिए गए हैं, उनके नाम हैं रामी रेंजर और हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट। इनमें से एक से बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बात करने और दूसरे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए सम्मान छीना गया है। सम्मान वापस लेने की घोषणा 'लंदन गजट' में की गई। रामी रेंजर और अनिल भनोट ने इसकी आदेश की घोषणा की निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारतवंशी ब्रिटिश नागरिक और करोड़पति रामी रेंजर को सीबीई (कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर) और लीसेस्टर में सामुदायिक कला केंद्र संचालित करने वाले अकाउंटेंट अनिल भनोट को ओबीई (ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर) की उपाधि दी गई थी। इन सम्मानों की जब्ती एक समिति की रिपोर्ट पर की गई है। यह जब्ती समिति उन मामलों पर विचार करती है, जिनमें सम्मान धारक को सम्मान प्रणाली को बदनाम करने वाला माना जा सकता है। जब्ती समिति की सिफारिशें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के जरिए राजा को सौंपी गई थी। इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में ओबीई सम्मान पाने वाले अनिल भनोट ने कहा कि जनवरी में जब्ती कमेटी ने उनसे संपर्क किया था। मैंने उसके सामने अपना पक्ष रखा था। भनोट के मुताबिक उन पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाने वाली शिकायत 2021 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में थी। भनोट ने कहा कि उस समय बांग्लादेश में हमारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था और हिंदुओं पर हमला किया जा रहा था। लेकिन मीडिया ने इसकी कवरेज नहीं की। मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और न ही मैंने सम्मान प्रणाली को बदनाम किया है। भनोट ने यह भी कहा कि इंग्लैंड में अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अतीत की बात हो गई है। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक और ब्रिटेन में एफएमसीजी फर्म सन मार्क लिमिटेड के संस्थापक लॉर्ड रामी रेंजर के प्रवक्ता ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि रामी इस फैसले को चुनौती देंगे। रामी रेंजर को दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दिसंबर 2015 में ब्रिटिश व्यापार और एशियाई समुदाय के लिए की गई सेवाओं के लिए सीबीई सम्मान से सम्मानित किया था। रेंजर ने कहा कि मुझसे यह सम्मान इसलिए वापस लिया गया क्योंकि मैंने भारत को तोड़ने का इरादा रखने वाले खालिस्तान समर्थकों और बीबीसी का विरोध किया था। यहां सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ब्रिटेन में अलगाववादियों और आतंकियों को खुले आम शरण दी जाती है। वो चाहे करते और बोलते हैं। लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। जबकि पीड़ितों के पक्ष में बोलना किसी सम्मान को बदनाम करना कैसे हो गया। इन दिनों बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। वो देश में खुले आम मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मौन हैं। उनकी अवॉर्ड वापसी पर कोई नहीं बोल रहा है, क्यों?

## नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

# बुजुर्गों के मानवाधिकारों के लिए राष्ट्रपति की चिंता के अर्थ

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वृद्धजन पर चिंता जाहिर की हैं। उनकी चिंता बहुत उपयुक्त है। वह भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित विश्व मानव अधिकार दिवस पर वृद्धजन के अलावा बहुत से दूसरे मुद्दे थे, उस पर बोलकर चली जातीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह एक नए विमर्श की ओर पूरे भारत का ध्यान खींची हैं। बृद्ध लोग आज भारत में उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। वे अपने जीवन में चुनौती को किसी को शेयर भी नहीं कर पाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह चाहती हैं कि इस बृद्ध तबके के बारे में सोचना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने इसीलिए मानव अधिकार आयोग के इस विशेष आयोजन और अवसर पर कह दिया कि वर्ष 2022 तक भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी और वर्ष 2050 तक इसके 35 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। वृद्ध लोगों की अमूल्य अंतर्दृष्टि और जीवन-अनुभव ऐसी संपत्ति हैं जो हमारे समुदायों को समृद्ध बनाती हैं। हमें उनके सामने आने वाले महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान निकालना चाहिए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सुरक्षा, सुरक्षा और सामाजिक समावेशन तक पहुंच शामिल है। वह जोर देकर कही हैं कि यह जरूरी है कि हम ऐसी नीतियां बनाएं और कदम उठाएं जो उनकी गरिमा को बनाए रखें और उनका कल्याण सुनिश्चित करें। उन्हें हमारे समाज के मूल्यवान सदस्यों के रूप में पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाएं।

भारत के राष्ट्रपति के इस स्टेटमेंट के बहुत मायने हैं। भारत में जहाँ वृद्धों को सदियों से आदर मिलता रहा है उसी देश में जब कोई बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार होता है, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। आज के बुजुर्ग किसी समय वे बच्चे थे। वे कभी युवा थे। वे कभी देश के निर्माण में अहम् भूमिका अदा करके बूढ़े हुए हैं। उनके ये हालात हैं, कि वे अपने आपको दीन-हीन महसूस कर रहे हैं। यह उनकी दशा नई पौध कर रही है। उनके अपने लोग कर रहे हैं। लगभग तीन साल पूर्व की बात है। एक बूढ़ी स्त्री जिसके दो बच्चे थे। वे विदेश में रहते थे। उस वृद्ध स्त्री की अहमदाबाद के एक घर में मृत्यु के तीन दिन बाद जब दुर्गंध आने लगी तो दरवाज़ा तोड़ा गया और लोगों को पता चला कि इस घर में रहने वाली बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। उसके आसपास के लोगों ने पहले बेटे को फोन किया। वह आने से मना कर दिया। उसकी एक बेटी थी। उसे फोन किया गया। उसने कहा अब आने से क्या फायदा है? अंतेष्टि के समय व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके दिखा देना। उसकी अंतेष्टि किसी और ने की बेटी ने उस बूढ़ी माँ का ऑनलाइन अंतिम संस्कार देखा।

विचित्र स्थिति है हिंदुस्तान की। भारत में एक श्लोक की चर्चा हर समागम में संतजन करते हैं 'अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्ध्यनते आयुर्विद्या यशो बलम। यह सदाचार की बातें हैं। सदाचार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण उक्ति है। यहाँ माता-पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की बातें बताई गई है। आज सोचने की

बात यह है कि क्या अब सदाचारी पीढ़ी अपने अवसान पर है। अनेक स्थानों पर वृद्धजन को घर से निकालने, उन्हें आश्रम पहुंचा देने, उन्हें त्याग देने और उन्हें प्रताड़ित करने की जो घटनाएँ सुनाई देती हैं। वे घटनाएँ किसी सदाचारी पीढ़ी से तो कम से कम नहीं घटतीं। जब देश में कोई भी जवां दंपत्ति अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके अपने सपने होते हैं। उनके अपने खुशियों का अम्बार होता है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शास्त्रों में कही गयी बातें, उन्हें नहीं सुहातीं। वे बिल्कुल स्वार्थी हो जाते हैं। एकांगी हो जाते हैं। न्यूक्लियर लाइफस्टाइल के पक्षधर बन जाते हैं। अपने परिजन के साथ घृणा करते हैं। अपने जीवन को संकुचित कर देते हैं। यह संकुचन बहुत ही नुकसान कर रहा है। यह संकीर्णता हमारे वृद्धों के हितों, उनके जीवन की प्रसन्नताओं और उनके अपने कि अनगिनत अन्तहीन टकराव व युद्ध, जलवायु परिवर्तन और अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून की घोर उपेक्षा की वजह से, वर्ष 2025 में साढ़े 30 करोड़ लोगों को जीवनरक्षक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह आंकड़ा भारत के लिए भी लागू होता है क्योंकि युद्ध न सही, जलवायु परिवर्तन का असर तो होगा ही। जलवायु परिवर्तन से हमारे वृद्धजन को प्राणरक्षक संसाधनों की ज़रूरतें पड़ेंगी ही पड़ेंगी। जीवनरक्षक सहायता की हमें मात्र तब और दुरुस्त करनी पड़ेगी, जब हमारे यहाँ वृद्धजन की संख्या बढ़ेगी।

जलवायु परिवर्तन तो एक अंतहीन लड़ाई बन गयी है। अब कॉप-29 से निकले विश्व भर के नेता चिंता में पड़े हैं कि स्थितियों को काबू में कैसे किया जाए। कैसे जीवनरक्षक सतत जीवनचर्या को स्थापित किया गरिमा को खंडित कर चुकी है। वृद्धों के साथ इस प्रकार का किस्सा निःसंदेह किसी भी संवेदनशील के लिए चुनौतीपूर्ण है।

देश में वृद्धाश्रमों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। त्यक्त लोगों की संख्या बढ़ेगी। चुनौतियाँ वृद्धों को लेकर गहराएँगी। समझने वाले लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संकेत को समझ जाएँ। उनका बतौर राष्ट्रपति इशारा ही काफी है कि अभी बुजुर्गों की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी और वर्ष 2050 तक इसके 35 करोड़ तक होगी। सोचिये फिर क्या होगा? सोचिये यदि हम आज उनके लिए अच्छा नहीं सोच सके तो भारत अपने वृद्धजन को लेकर कितनी परेशानियों का सामना करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी टॉम फ़्लैचर ने आगाह किया था जा सके। वृद्धों की बढ़ती आबादी इस क्लाइमेट चेंज से ज्यादा प्रभावित होने वाली है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा था कि वृद्धजन की गरिमा और मानवाधिकारों का संरक्षण करने, और समाज में उनके सामने चुनौतियों से निपटने में, पूरी मानवता का लाभ है। अन्तरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी वृद्धजन के लिए ऐसा वादा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र के आलोक में किया गया था, उसका स्मरण आता है। एक यूएन रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वर्ष 2050 में, दुनिया भर में, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग दोगुनी होकर एक अरब 60 करोड़ हो जाएगी। भारत में यदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह कह रही हैं कि 2050 तक इसके 35 करोड़ बूढ़े केवल भारत में होंगे तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है अपितु जिस प्रकार से वृद्धजन की संख्या बढ़ी है उसे वह ध्यान में रखकर बात कर रही हैं।

मानवाधिकार संस्थानों, सिविल सोसायटी और प्रासंगिक हितधारकों से, सार्वभौमिक घोषणा-पत्र को, वृद्धजन के लिए समर्पित बनने का आह्वान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता रहा है। एनएचआरसी ने हाल ही में विधवाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। निःसंदेह भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार पर्याप्त नए कदम उठा रहा है। वृद्धों के लिए कुछ विशेष हो, राष्ट्रपति की इस चिंता व्यक्त करने के बाद तो निश्चय ही राष्ट्रपति मुर्मू के कहने का वह प्रतिफल होगा। कार्यवाहक अध्यक्ष विजया सायानी और महासचिव भरत लाल ने इस बीच कई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय मानव अधिकार आयोग में कार्य किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वयं दूसरों के कल्याण के लिए अध्यक्ष, महासचिव और पूरे आयोग की अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण और सेवा के लिए प्रशंसा की है, यह अच्छी बात है लेकिन जो उन्होंने आह्वान किया है कि आइए हम न्याय, समानता और गरिमा के मूल्यों के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए, हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे न छूटे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत के मानवाधिकारों में अभिवृद्धि देखने वाले लोगों, आयोग, सिविल सोसायटी और प्रासंगिक हितधारकों के साथ सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में विश्वास व्यक्त करने वाले लोगों का अब दायित्व है की वे वृद्धों के हित को ध्यान रखें और उनके जीवन में प्रसन्नता का भोर लाएं।

## आर्थिकी

राजकुमार सिन्हा

लेखक 'बरगी बांध विस्थापित संघ' के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

# साथ-साथ बढ़ती भुखमरी और समपन्नता

हमारी प्रगति की परीक्षा यह नहीं है कि हम समृद्धि में और वृद्धि करते हैं, बल्कि यह है कि हम उन लोगों के लिए पर्याप्त प्रदान करते हैं, जिनके पास बहुत कम है।' - फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। वित्त वर्ष 2024 की विश्व अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में भारत 5 वें स्थान पर पहुंच गया है। देश की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है जो एक दशक पहले 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी। यह 10वीं बडी अर्थव्यवस्था की स्थिति से एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है, परन्तु सवाल उठता है कि इस प्रगति का लाभ हर किसी तक पहुँच पा रहा है या नहीं। खासकर उन लोगों तक जो हाशिये पर हैं, जबकि देश की 80 करोड़ आबादी केन्द्र सरकार के पांच किलो आनाज पर निर्भर है।

वर्ष 2024 के 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (वैश्विक भूख सूचकांक) में कुल 127 देशों में भारत 105 वें स्थान पर है जो इसे भुखमरी की गंभीर श्रेणी में रखता है। पड़ौसी देश श्रीलंका (56), नेपाल (68) और बांग्लादेश (84) की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत की कुपोषित आबादी 13.7 प्रतिशत है, अर्थात अनुमानित 20 करोड़ आबादी कुपोषित है। भारत में 5 साल से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चों का कद कम है,18.7 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और 2.9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं। विश्व के सभी 127 देशों में से सिर्फ़ भारत ने ही इन आंकड़ों को नकारा है।

'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और 'ट्रैक' करने का एक औजार है। यह सूचकांक आयरिश मानवीय संगठन 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' और जर्मन सहायता एजेंसी 'वेल्थुंगरहिल्फ' द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरी तरफ विगत 5 सालों में भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी हो गई है। वर्ष 2024 में भारत के टॉप 100 अमीरों की कुल

संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर के पार, अर्थात् 92 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2023 के मुकाबले इनकी कुल संपत्ति में 26.50 लाख करोड़ रुपये की बढोत्तरी हुई है और 2020 की तुलना में इनकी अमीरी दो-गुनी से ज्यादा हो गई है। इस साल 100 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति बढ़ने में उनके बिजनेस से मुनाफे में बढोत्तरी से ज्यादा शेयरों में तेजी का योगदान रहा है। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है, जहां शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय सम्पत्ति का 77 प्रतिशत है। देश के सबसे समृद्ध 1 प्रतिशत के पास 53 प्रतिशत संपत्ति मौजूद है, जबकि जनसंख्या के आधे गरीब हिस्से के पास राष्ट्रीय संपत्ति का मात्र 4.1 प्रतिशत के बराबर है।

देश के कुल 'वस्तु एवं सेवा कर' (जीएसटी) का लगभग 64 प्रतिशत निचली 50 प्रतिशत आबादी से प्राप्त होता है, जबकि इसमें शीर्ष 10 प्रतिशत का योगदान मात्र 4 प्रतिशत है। गरीबों पर लादे गए टैक्स बोझ से यह अर्थव्यवस्था गुलज़ार है। रोजगार विहीन विकास की सच्चाई तो 'इंडिया एम्पलायमेंट रिपोर्ट 2024' ने खोलकर रख दिया है। 'इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन' (आईएलओ) ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट' के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं जिनमें ज्यादातर शिक्षित हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 में पढे-लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2 प्रतिशत थी जो 2022 में बढकर 65.7 प्रतिशत हो गई है। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या 48.4 फीसदी थी, जबकि पुरूषों की मात्र 9.8 फीसदी यानि बेरोजगारों में महिलाएं 95 फीसदी थीं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 के बाद से औपचारिक रोजगार का अनुपात लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2018 के बाद इसमें भारी गिरावट आई है। ठेके पर आधारित नौकरियां में इजाफा हुआ है, जबकि बहुत कम लोग नियमित और लंबी अवधि के अनुबंध वाली नौकरियों में हैं।

'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (एनसीआरबी) से पता चलता है कि वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 5207 किसान और 6083 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। यह दर्शाता है कि इस विकास में आम भारतीयों की भागीदारी बहुत ही नाममात्र की है। दूसरा भुखमरी पर बढती आबादी का तर्क थोप दिया जाता है, कहा जाता है कि एक सौ चालीस करोड़ लोगों का पेट भरना आसान काम नहीं है। जाहिर है, इसी मशक्कत में कई लोगों को भुखमरी बर्दाश्त करना पड रहा है, जबकि अनाज भंडारण की कमी के कारण देश में साल-दर-साल सडते और बर्बाद होते अनाज को लेकर समाधान निकालने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। अनेक अध्ययनों और शोध से पता चलता है कि घटता उत्पादन, भुखमरी और आबादी का कोई सबंध नहीं है। इसकी वजह तत्कालीन आर्थिक, राजनैतिक नेतृत्व है।

सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि भारत में हम मुक्त बाजार बनाते-बनाते कुछ और ही कर बैठे? मुक्त अर्थ व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बाजार को ताकतवर बनाना था मगर यहां तो मुक्त बाजार की ताकत ही कुछ चुनिंदा हाथों में रह गई है। यहाँ एक तरफ बेरोजगारी, असमानता, महंगाई है दूसरी तरफ मोनोपोली वाले शेयरों की कमाई है।

ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोआन रोबिंसन ने इसे ही 'इम्परफेक्ट मार्केट' कहा है। यह बेईमान बाजार है, जो एक तरफ से उपभोक्ताओं की जेब काटता है और दूसरी तरफ कामगारों को उनकी काबिलियत और मेहनत से कम पैसा देता है। अलबत्ता शेयर निवेशकों के लिए यह परफेक्ट है। इसलिए वृहद समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और व्यापक सरकारी कार्यवाहियों की आवश्यकता होगी। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इस विकास का मानवीय चेहरा धुंधला पड जाएगा। (सप्रेस)

# अस्थायी जीवन में केवल व्यवहार स्थायी

## अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

जो आता है उसका जाना निश्चित है। यह तो हम सबने सुना है और इस बात की सच्चाई से भी हम भली-भांति अवगत है। समय चक्र के इस फेर से कभी कोई भी बच नहीं पाया लेकिन फिर भी हम यह बात समझ ही नहीं पाते कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम छोटी से छोटी उपलब्धि के वर्षों बाद भी अपनी मेहनत को याद नहीं रखते। याद रखते है तो बस उस रसूख को जो हमें कुछ ही क्षणों के लिए मिलती है। हम भूल जाते है कि यह शान हमारी हमेशा के लिए नहीं है। कल कोई और हमसे भी ज्यादा मेहनत करके हमारी जगह पर बैठ सकता है।

हम अपने विरोधियों को नीचा दिखना चाहते है या हम अपने से उम्र या ओहदे में छोटो को ज़बरदस्ती का ज्ञान देने लगते है। इससे भी बढ़कर जब हमसे कोई सलाह लेता है तब तो हम उसकी गलतियां गिनाने लगते है। हम भूल जाते है कि यदि हमसे कोई सलाह चाहता है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, बल्कि इसका अर्थ है कि उसे हमारे द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान है। पर हम तो अपने ही अहंकार में चूर होते है। हम उसे ही सलाह के नाम पर नीचा दिखाते है जो हमारे शब्दों का मान रखता है। जो हमारी बात से उपर अपनी बात को महत्व दें , ऐसे लोगों को सलाह देने से हम कतराते है।

हम जानते है कि वहां हमारी दाल नहीं गली, उलटा ऐसे ही लोगों का हम उदाहरण देते है। देखो फलाना कितना समझदार है। हम यह कभी नहीं कहते कि तर्कों की आड़ में वह हमारी बात को ही काट कर अपनी बात मनवाता है। हम तो यह दिखाना चाहते है कि सामने वाला तार्किक है, इसलिए हम उसकी बात का मान रखते है। जबकि सच को हम छिपाना भी चाहे, तब भी वह ज़्यादा देर तक नहीं छिपता।

हर सफल इंसान के भीतर यह भावना होती है कि उसकी मेहनत के कारण जिस सफलता को वह आज जी रहा है, वह उसके बारे में बात करें, दूसरों को भी रास्ता दिखाए। लेकिन रास्ता दिखाते-दिखाते हम दूसरों का अपमान करने को ही अपनी सलाह देने का तरीका बना लेते है।

हम क्यों नहीं यह समझते कि सब कुछ अस्थायी है। हमारी सफलता, हमारा जीना, हमारा ओहदा, हमारा रूतबा सबकुछ किसी भी समय किसी ओर का हो सकता है। हमें अपनी सफलता से किसी दूसरे के लिए भी रास्ता बनाना चाहिए। हमें अपने हर कदम को रखते हुए, अपने द्वारा की गई मेहनत के उन क्षणों को याद करना चाहिए। उस हर पल का धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा ने आपको दूसरों की सहायता के काबिल बनाया।

इस अस्थायी जीवन में आपका नाम आपके व्यवहार के कारण स्थायी रह सकता है। कठिन परिश्रम से मिली सफलता के हाथी का महावत बनाना तो आसान है, लेकिन सफलता रूपी हाथी बनना कठिन है, हाथी वही बन सकता है जो धीमे-धीमे चलकर अपनी मंजिल को भी पा लें, और धैर्यता से अपने साथियों के साथ-साथ बिना उन्हें नीचा दिखाए अपने से छोटों को के लिए भी रास्ता बनाए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**
उमेश त्रिवेदी
**कार्यकारी प्रधान संपादक**
अजय बोकिल
**संपादक (मध्यप्रदेश)**
विनोद तिवारी
**वरिष्ठ संपादक**
पंकज शुक्ला
**प्रबंध संपादक**
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

## व्यंग्य

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

# ऑफर की ताक में भिया लोग

त्योहारों के मौसम हो, और बाजार में ऑफर न हो। ऐसा कभी हुआ है? ऑफ़र तो कौड़ियों के मोल मिलते हैं। हर दुकान, शोरूम और प्रतिष्ठानों पर स्लोगनों, टैग लाइन की बाढ़ सी रहती है। इस बाढ़ में मानव मन डूबने से बच नहीं पाता। दिमाग काम नहीं करता और सोचने-समझने की शक्ति का हरण हो जाता है। जो व्यक्ति बाजार में जाकर ऑफर का अनादर करता है, उसे बाजारवाद की भाषा में अनुदार कहा जाता है।

बाजारवाद के इस समंदर में सिर्फ गोते लगाने से काम नहीं चलता, इसमें जनता को तैरना भी आना चाहिए। जो इसमें तैर जाता है वह कई ऑफरों के रत्न लेकर ही बाहर आता है। अभी-अभी बीते त्योहारी सीजन की एक घटना ने सच में दिमाग को सुन्न कर दिया। बाइक के शोरूम पर सबसे आकर्षक ऑफर तो मुझे पांच लीटर ईंधन फ्री वाला लगा। काश! इसे मासिक कर दिया जाता तो...। लाड़ली बहना की तरह देश और राज्य के सारे भिया लोग भी खुश म खुश हो जाते और सरकार के गुण गाते नहीं अघाते। सरकार की बुनियाद में अब लाड़ली बहना का आशीर्वाद रूपी कंक्रीट भरा हुआ है। जिसे दूसरे ऑफर हिला भी नहीं सकते। अब जब भी छोटे या बड़े चुनाव होते हैं, महिला मंडल साड़ियों के ऑफर नकार देती हैं। कई महिलाएं तो यह कहने से नहीं चूकती कि अब तो 'केश' का जमाना है। वह भी ऑन लाइन, चाहे वह बैंक के माध्यम से आए या फिर ऑनलाइन पेमेंट एप्स के वॉलेट से।

जब से एक प्रदेश में बहनाओं के लिए ऑफर शुरू हुआ तो यह अन्य राज्यों में भी महामारी की तरह संक्रामक होकर फैल गया। इस संक्रमण के चलते वहां भी अपना चमत्कार दिखा ही दिया। अब तो दिल्ली दरबार भी इसे स्थायी योजना बनाने पर तुला हुआ है। सबकुछ बहनों के लिए। कहीं भियाओं की त्योरी तन गई तो? खैर, अब देखिए न ऑफर और रेवड़ी में बहुत साफ फर्क है। रेवड़ी पर बदनामी का इतना ठीकरा फोड़ा गया कि लोग अब दुकान पर भी रेवड़ी रखने और खरीदने से कतराने लगे हैं। तिल्ली और शकर की चाशनी के मिश्रण से ठीक वैसी बनी रेवड़ी, जैसे पार्टियों के गठबंधन होते हैं। अब अपनी साख गंवा चुके हैं। लोग भी अब रेवड़ी के बजाय गजक के चक्कर में रहते हैं। यही गजक नए रूप में नकद ऑफर के अवतार में जग का कल्याण करने के लिए आई हुई है। बहनाओं के साथ किसान भी तो हर महीने मिलने वाली राशि के ऑफर के चक्कर में एमएसपी भूलते जा रहे हैं। अब उन्हें आय दुगनी करने की आवाज भी अंतर आत्मा में सुनाई नहीं देती। युवा वर्ग तो बेचारा फ्री फायर खेलते-खेलते इस फायर की चपेट में आ गया है। अब उन्हें अग्निवीर कहलाने में गर्व हो रहा है। भले ही चार साल बाद वे वापस फ्री होकर फ्री फायर खेलते नजर आएंगे, लेकिन इस ऑफर को भी वे असेप्ट कर रहे हैं।

पहले के जमाने में कर्ज लेना बुरा माना जाता था, लेकिन ऑफर युग में कर्ज लेना अपनी कॉलर खड़ी करने का माध्यम है। जो जितना अधिक कर्ज लेगा वह उतना समृद्ध राज्य कहलाएगा। अब सभी राज्य इस होड़ में दौड़ रहे हैं। बेचारे विद्यार्थी पसोपेश में हैं कि एक तो टीचर की मार और माता-पिता की डांट खाकर 80 से 90 परसेंट नंबर लेकर आए, लेकिन उनकी प्रोत्साहन योजना कहीं दूर बैठकर सिसक रही है और बच्चे लेपटॉप और बालिकाएं स्कूटी के लिए आंखे फाड़-फाड़ के देख रही हैं। सरकार है कि इस ऑफर के मामले में टस से मस नहीं हो रही है। इधर, ये सब चल रहा है, सरकारें बन रही है, लेकिन मुख जैसा मुखिया रेत में सुई ढूंढने के समान हो गया है। ऑफर के दम पर सरकार बन तो गई। किसान की सरसों नहीं पकी। इधर, नेताजी भी किसी ऑफर की तलाश में हैं, उनके कुर्ते पर लिखा हुआ है, टिकाऊ हैं इसलिए तो बिकाऊ हैं, कोई ऑफर तो करे...।

योग नगरी

मुकेश अग्रवाल

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)



# सांस्कृतिक सम्मोहन में खींची, दुनिया की योगनियां

**योग नगरी ऋषिकेश से कोई चालीस किलोमीटर की दूरी पर बसे सिंगथाली गांव के निकट बड़ी संख्या में विदेशी साधकों का हुजूम लगा था। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका,इंडोशिया, ईरान, ताइवान, चीन यहां तक कि पाकिस्तान से योग के जिज्ञासु भी शामिल थे। गांव के ठीक नीचे पुण्य सलिला गंगा की लहरों का अंतर्मन को भिगोना वाला संगीत साधकों को सम्मोहित कर रहा था।**

जैसे ही सूर्य की रश्मियां टिहरी गढ़वाल की इस तलहटी में नवजीवन का संचार करने लगी, ये तमाम विदेशी योगी-योगनियां अपने तांबे, चांदी व मिश्रित धातुओं के पात्रों से सूर्य को अर्घ्य देने लगते हैं। ये क्रम निरंतर कई घंटों तक चलता है। दरअसल, ये विभिन्न देशों, संस्कृतियों व धर्मों के साधक जल साधना के जरिये ध्यान की एकाग्रता का लक्ष्य हासिल कर रहे थे। साम्यवादी चीन, लोकतांत्रिक ताइवान, कठमुल्ला संस्कृति के वाहक ईरान व पाकिस्तान के विभिन्न धर्मी लोगों को सूर्य को अर्घ्य देते देखना रोमांचित करता है। ये योग की जोड़ने की संस्कृति का जीवंत प्रमाण ही है।

गंगा की धारा के मध्य एक दिव्य योगी का सूर्य को अर्घ्य देते हुए जल साधना करना योग साधकों को रोमांचित कर जाता है। उनके साथ एक ब्रिटिश साधक परछाया की तरह सदैव मौजूद रहते हैं। बेंगलुरू स्थिति योग अनुसंधान संस्थान अक्षर योग केंद्र के सूत्रधार हिमालय सिद्ध अक्षर की उपस्थिति योग साधकों को रोमांचित कर जाती है। पिछले वर्षों में आधा दर्जन से अधिक आसनों के प्रदर्शनों के जरिये विश्व विख्यात गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपस्थिति दर्ज करा चुके हिमालय सिद्ध अक्षर के अनुयायियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गंगा के तट पर मार्गदर्शन कर रहे योगी व योगनियों का श्रद्धा व विश्वास से निरंतर सूर्य को अर्घ्य देने एक सुखद अनुभव दे जाता है।

निस्संदेह, यह योग की ताकत ही है दुनिया की अलग-अलग शासन व्यवस्थाओं, विभिन्न महाद्वीपों, संस्कृतियों व धर्मों से जुड़े लोग यहां श्रद्धा भाव से यौगिक क्रियाओं को संपन्न कर रहे थे। उनके लिये योग व ध्यान की समृद्ध परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बाधक नहीं है। ये योग की वैश्विक सर्व स्वीकार्यता है कि इन युवा योग साधकों को भारत की धरती सम्मोहित करती है। ये अद्भुत सांस्कृतिक मेला नजर आता है। इस विशिष्ट योग सम्मेलन में भाग लेने वालों में कॉरपोरेट जगत के बड़े अधिकारी शामिल हैं। उनमें एक नवविवाहित युगल, एक भरा-पूरा परिवार, एक प्रेमी युगल, एक विवाह को तिलांजलि देकर आई आत्मनिर्भर युवती और एक सत्तर वर्षीय चीनी महिला भी शामिल रही। वे न केवल गंगा के महात्म्य के साथ योग साधना करते रहे बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति खान पान व रीति रिवाजों से भी परिचित होते रहे। उन्होंने उत्तराखंड के रीति-रिवाजों व संस्कृति में खासी रुचि दिखायी। उन्हें तमाम विदेशी व्यंजनों के बजाय उत्तराखंड के परंपरागत खाद्य पदार्थ व मिठाइयां रास आई। खानपान में मंडवे का डोसा, अरसे, स्वाली और आलू-मूली की थिचौंडी उन्हें अपने विशिष्ट स्वाद के लिये प्रभावित करती रही।

पिछले दिनों ताइवान की यात्रा से लौटे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हिमालय सिद्ध अक्षर बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग को मान्यता देने से इसकी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। लोग लगातार अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा के बजाय योग व प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि ले रहे हैं। भारत को योग की जन्मस्थली की रूप में स्वीकार्यता मिल रही है। वे बताते हैं कि इस योग रिट्रीट में साधकों को आसन, प्राणायाम व ध्यान के साथ योगदर्शन के आध्यात्मिक पक्ष से भी अवगत कराया गया। ये योग साधक मशीनी होती जिंदगी की ऊब से मुक्त होने के लिए भारत आते हैं। सही मायनों में योग हमारे मनोकायिक रोगों में एक अचूक दवा का काम करता है।

दरअसल,रोग हमारे मन के दोषों से भी पनपते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल दिमाग को प्रदूषण से मुक्त करके योग साधना से सुकून हासिल करना उनकी प्राथमिकता है। वे आसपास के गंगा से जुड़े तीर्थों तक पहुंचे। देवप्रयाग का तीर्थाटन उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। एक पूरे दिन उन्होंने संगम पर जल साधना के जरिये आध्यात्मिक साधना के अविस्मरणीय अनुभव हासिल किये। निश्चय ही भारत से पवित्र अहसास लिये ये साधक कालांतर अपने अपने देशों में भारत के सांस्कृतिक दूत की भूमिका निर्वहन करेंगे। सिंगथाली के सुरम्य प्राकृतिक अधिवास में गंगा का सानिध्य इन विदेशी योग साधकों को भावविभोर कर गया। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुषमा उन्हें मंत्रमुग्ध कर गयी। इस पंद्रह दिन को योग पर्व में उन्होंने योग की विभिन्न आयामों से रूबरू होने का शुभ अवसर पाया और इसका भरपूर लाभ भी उठाया।

प्रातः कालीन सत्र में आसन, प्राणायाम व ध्यान, दिन में योग जिज्ञासाओं पर मंथन और रात्रि के सत्रों में योग के बौद्धिक विमर्श में इन विदेशी मेहमानों ने सक्रिया भागेदारी निभायी। इन विदेशी साधकों की योग जिज्ञासाओं के निराकरण के लिये कई विशेष सत्र भी इस दौरान आयोजित किए गए। वहीं गंगा के तट पर रोज होने वाली संध्या कालीन गंगा आरती इन साधकों के लिये एक पर्व जैसा होता था। घाटी की गहराई में पहाड़ी इलाका होने के कारण सूर्य जल्दी ही ओझल हो जाता है ऐसे में आरती में प्रयुक्त होने वाला कई ज्योतियों वाली दीप माला इन विदेशी मेहमानों को रोमांचित कर जाती है। वे फिर अपनी योग साधनाओं में गहरे उतर जाते।

हिमालय सिद्ध अक्षर बताते हैं कि योग को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद दुनिया के लाखों साधक भारत आकर योग की जन्मभूमि से रूबरू होना चाहते हैं। दरअसल, भौतिक सुखों की विसंगतियां इनको उपभोक्तावादी संस्कृति से विमुख कर रही है। वे सुकून की तलाश में योग की जन्मभूमि भारत इसके सम्मोहन में बंधे चले आते हैं। यह क्रम सालों साल चलता रहता है। उन्हें भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व धार्मिक सीमाएं बांध नहीं पाती। विडंबना यह है कि विदेशों में लोग जिस भौतिक संस्कृति का परित्याग करने को प्रयासरत हैं, भारत में उसका अनुकरण शान समझा जाता है। ऐसे में योग का सानिध्य हमें सुखमय जीवन की राह दिखाता है।

---

मानसिक स्वास्थ्य

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

वरिष्ठ मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषक हैं।



# प्रेरणामद: एक नशा जो कर रहा है जिंदगी पर कब्जा

क्या आप भी सोचते हैं कि एक और रील देखने के बाद काम शुरू करेंगे? सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल रील्स की बाढ़ आ चुकी है। सुबह उठते ही लोग रील्स देखने लगते हैं और सोने से पहले भी वही करते हैं। खुद को प्रेरित करने के चक्कर में वे अनजाने में प्रेरणामद का शिकार हो जाते हैं।

प्रेरणामद क्या है?

यह शब्द मैंने (डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी) ने गढ़ा है। यह दो शब्दों 'प्रेरणा' और 'मद' (नशा) से बना है। इसका अर्थ है ङ्क मोटिवेशनल रील्स और कंटेंट का ऐसा नशा, जो आपको प्रेरणा का झूठा अहसास देता है, लेकिन असल जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाता।

इसी अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पेश करने के लिए मैंने एक और शब्द गढ़ा – Motiveto&icationÐ यह Motivation + Into&ication का मेल है और इसका मतलब भी वही है– मोटिवेशन का नशा।

इस लेख का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि प्रेरणामद (Motiveto&ication) कैसे काम करते हैं, कैसे ये आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं और इस जाल से बाहर कैसे निकला जा सकता है।

प्रेरणामद कैसे आपकी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहा है?

क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन के 2–3 घंटे सिर्फ रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं? आप सोचते हैं, 'बस 5 मिनट और,' और फिर देखते ही देखते 1–2 घंटे गुजर जाते हैं।

इस आदत का असर आपकी कार्य क्षमता, मानसिक शांति और फैसले लेने की क्षमता पर पड़ता है। जो समय आपको काम करने में लगाना चाहिए था, वह सिर्फ रील्स देखने में चला जाता है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, जबकि असल में कुछ भी नहीं बदला।

कैसे पता करें कि आप प्रेरणामद के शिकार हो चुके हैं?

अगर आप नीचे दिए गए लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी प्रेरणामद या Motiveto&ication के शिकार हों–

**समय की बर्बादी:** आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट देखूंगा, लेकिन 1–2 घंटे कैसे निकल गए, पता ही नहीं चलता।

**काम टालना:** हर बार काम करने से पहले 'थोड़ी प्रेरणा' लेने के लिए रील्स देखने लगते हैं।

**फर्जी आत्मसंतोष:** आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, लेकिन असल में आपने कुछ नहीं किया।

**तनाव और आत्म-संदेह:** बार–बार मोटिवेशन के बावजूद, जब परिणाम नहीं मिलता, तो आप खुद को दोषी मानने लगते हैं।

कैसे फंस जाते हैं लोग प्रेरणामद के जाल में?

यह प्रक्रिया बेहद साधारण है और बिना जाने ही आप इस चक्र में फंस जाते हैं।

**मुश्किल काम टालना:** जैसे पढ़ाई, ऑफिस का काम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट।

**प्रेरणा की तलाश:** आप सोचते हैं, 'पहले थोड़ा मोटिवेशन ले लेता हूं।'

**रील्स देखना शुरू करते हैं:** आपको पहली रील में मजा आता है।

**डोपामाइन रिलीज होता है:** रील देखकर मस्तिष्क में 'डोपामाइन' रिलीज होता है, जो आपको ताजगी का अहसास कराता है।

**एक और रील देखने की इच्छा होती है:** आप दूसरी रील देखने लगते हैं।

**टाइम की बर्बादी:** 2–3 घंटे यूं ही गुजर जाते हैं और काम अधूरा रह जाता है।

यही है प्रेरणामद का चक्र, जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं।

---

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।



# भावनाओं के वेग को जरा नई दिशा दीजिए ...

**बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो आजकल के दौर में आदमी का प्रैक्टिकल होना, आज के दौर की जरूरत बन गया है। यह स्थिति कुछ इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कि शराफत को कमजोरी ही समझ लिया जाए। दरअसल भौतिकता की चकाचौंध में आम आदमी की मानसिकता ही कुछ इस कदर बन गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय शख्सियत को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा है। यह आम अनुभव में आई हुई बात होती है कि राजनीति में सक्रिय रहने पर तमाम तरह के आक्षेप और समाज सेवा में सक्रिय रहने पर जमाने भर के गतिरोध, कर्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। इन क्षेत्रों में अच्छी से अच्छी उपलब्धियों का परचम चाहे लहरा दिया जाए, कलंक के छींटे से बच नहीं सकते। एक प्रकार से इन क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी भी निरापद नहीं रही। यही कारण है कि अनेक उदारमना परमार्थ की प्रबल भावना के बावजूद अपनी भावनाओं को मात्र भावना ही बने रहने देना चाहते हैं। यानी कि उसे क्रिया रूप में रूपांतरित नहीं किया करते।**

जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब कोई अति भावुकता में कोई निर्णय ले लेवें, लेकिन उसका अपेक्षित परिणाम सामने नही आए। और तो और ऐसे किसी निर्णय को स्वार्थ प्रेरित दृष्टिकोण निरूपित किया जाने लगे। तो बहुत स्वाभाविक है कि मन को बहुत कोफ्त होती है। दरअसल एकतरफा भावना भाने का आजकल के दौर में कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। यही कारण है कि जमाने की हवा को देखते हुए किसी समय के भावना प्रधान लोग भी अपने आचरण और व्यवहार को व्यावहारिक जामा पहनाने लगे हैं। बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो आजकल के दौर में आदमी का प्रैक्टिकल होना, आज के दौर की जरूरत बन गया है।

यह स्थिति कुछ इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कि शराफत को कमजोरी ही समझ लिया जाए। दरअसल भौतिकता की चकाचौंध में आम आदमी की मानसिकता ही कुछ इस कदर बन गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय शख्सियत को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा है। यह आम अनुभव में आई हुई बात होती है कि राजनीति में सक्रिय रहने पर तमाम तरह के आक्षेप और समाज सेवा में सक्रिय रहने पर जमाने भर के गतिरोध, कर्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। इन क्षेत्रों में अच्छी से अच्छी उपलब्धियों का परचम चाहे लहरा दिया जाए, कलंक के छींटे से बच नहीं सकते। एक प्रकार से इन क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी भी निरापद नहीं रही।

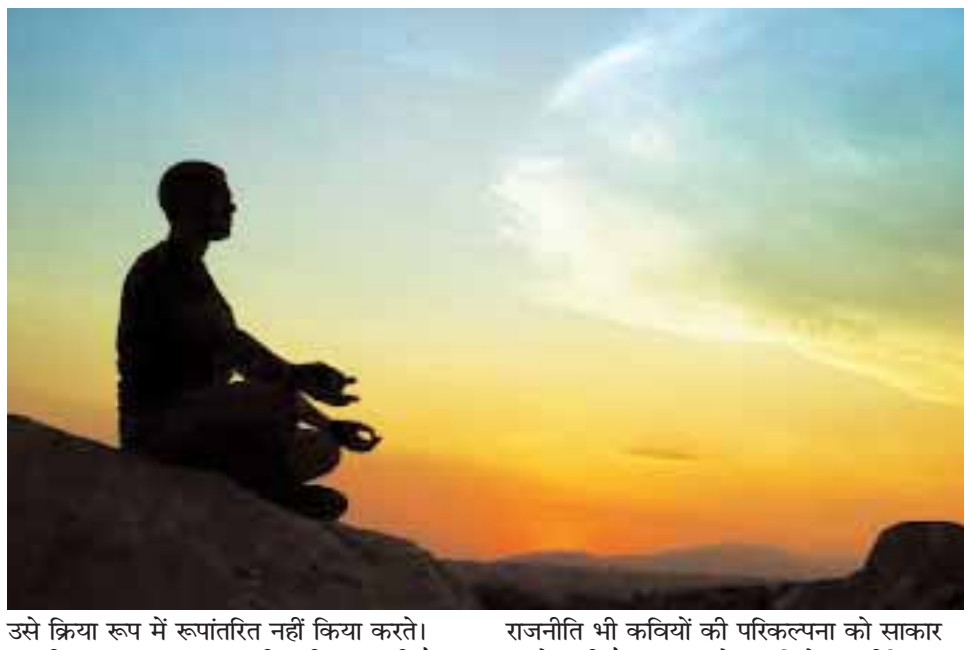

यही कारण है कि अनेक उदारमना परमार्थ की प्रबल भावना के बावजूद अपनी भावनाओं को मात्र भावना ही बने रहने देना चाहते हैं। यानी कि उसे क्रिया रूप में रूपांतरित नहीं किया करते। उनकी भावना बस भावना ही बनी रह जाती है। यह एक अनुभवजन्य तथ्य है कि समाज सेवा के प्रति प्रबल रूप से समर्पित मनोभाव भी ऐसे वातावरण में हतोत्साहित हो जाता है। आजकल राजनीति भी कवियों की परिकल्पना को साकार करने लगी है। वास्तव में इन दिनों राजनीति का सर्वव्यापीकरण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। यह जब चाहे तब चाहे जहां हो जाती है और चाहे जैसी हो जाती है। राजनीति से इतर भी राजनीति होती है, राजनीति के मायने राजनीतिक हथकंडों के रूप में लिए जा सकते हैं।

यह वह राजनीति नहीं होती जिसे आप और हम समझ रहे हैं। वास्तव में यह ऐसी राजनीति होती है जो इसे हटाओ उसे बैठाओ के रूप में जुड़ी होती है। कब, किस मामले में किस तरह की राजनीति हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। काश, कि राजनीति में ही राजनीति होती और कहीं नहीं होती! मुद्दे की बात यह है कि इन तमाम परिस्थितियों के चलते आदमी को अपनी भावनाओं के वेग को थाम कर चलना निहायत ही जरूरी है। जहां तक परोपकार की भावना का प्रश्न है, बिना सामने आए भी इस क्रिया को मूर्त रूप दिया जा सकता है। जिसके चलते लौकिक रूप से यश कीर्ति चाहे न मिलें, लेकिन अंतर्मन में असीम आनंद की दिव्य अनुभूति की जा सकती है।

वैसे भी समय, श्रम और धन का दान किसी अन्य के मानस पटल पर अंकित हो जाए या नगद दान की रसीद मिल जाए, तो यह तो एक प्रकार का 'विनिमय' ही होगा। वैसे भी बिना किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिफल की आशा के साथ किसी लोकोपयोगी क्रिया में दिया गया अंशदान ही सच्चे अर्थों में परोपकार की परिभाषा में शामिल होना चाहिए। एकदम निःस्वार्थ यानी कि विशुद्ध रूप से निःस्वार्थ। जिसमें प्रतिफल के नाम पर सिवाय आत्मिक संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। वैसे भी किसी भी प्रकार का दान देने की भावना अंतर्मन की आंतरिक भावनाओं का सैलाब ही हुआ करती है। अंतरंग की इस प्रसन्नता के सम्मुख भौतिक रूप से मान सम्मान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए।

ऐसा नहीं है कि जमाने की विपरीत हवा को देखकर परोपकार का भाव ही मन में हम नहीं लाएं। निश्चित रूप से परोपकार ही समस्त धर्मों का सार तत्व निरूपित किया जा सकता है। इसलिए अपनी उदार भावनाओं को केवल और केवल आत्मीय सुकून की दृष्टि से क्रियान्वित कर देना ही बेहतर होगा। इसके लिए किसी संस्था या किसी अन्य माध्यम की कतई आवश्यकता नहीं है। जब जहां जो सुपात्र नजर आ जाए, उसकी मदद कर देना ही काफी होगा। कल्पना कीजिए जब बिना किसी संस्था या अन्य माध्यम के ऐसा परोपकार होने लगेगा। तब परोपकारी के हजारों भाई बंधु होंगे, हजारों पुत्र पुत्रीवत होंगे। तब 'वसुधैव कटुंबकम' की परिकल्पना साकार हो उठेगी।

# ग्राम पंचायतों को क्रियाशील बनाया जाए : मुख्यमंत्री

**● विवाद रहित ग्राम पंचायतों को पांच-पांच लाख रुपए मिलेंगे ● आगामी 26 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान ● ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह की कोई समस्या शेष न रहे ● मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी से उज्जैन दक्षिण विधान सभा की ग्राम पंचायतों के सरपंचों से चर्चा की**

**भोपाल(नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहां है कि जिन ग्राम पंचायत में कोई विवाद नहीं होगा, जिन ग्राम पंचायत में कोई झगड़ा नहीं होगा, एक ग्राम पंचायतों को पांच - पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इन ग्राम पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को उज्जैन के एनआईसी कक्ष से वीसी द्वारा उज्जैन दक्षिण विधानसभा की ग्राम पंचायतों के सरपंचों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने वीसी में कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान आगामी 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण जनों को अवगत कराया जाएगा तथा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

**मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सभी पंचायतों को क्रियाशील बनाना है-** वीसी में उज्जैन कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले की 589 ग्राम पंचायतों में निरंतर कैंप लगाए जा रहे हैं। दक्षिण विधान सभा की सभी पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के द्वारा लैकोड़ा ग्राम पंचायत, तालोद ग्राम पंचायत के सरपंच से चर्चा की गई। बताया गया कि तालोद में फतेहाबाद तक की सड़क का निर्माण हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने वीसी में कहा कि सरपंच, ग्राम

पंचायतों में निरंतर भ्रमण करें। हितग्राहियों से चर्चा करें और उनकी समस्याओं को सुनकर, समय सीमा में उनका समाधान करें। वीसी में जानकारी दी गई की ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने ग्राम टंकारियापंथ के सरपंच और पटवारी से चर्चा की। ग्राम पंचायत उमरिया खालसा में जैन मुनियों के लिए अतिथि कक्ष भी बनवा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में अतिथि कक्ष बनवाया जाए। वर्तमान में जो वेब सीरीज बनाई जा रही है उनमें उज्जैन की ग्राम पंचायतों में भी शूटिंग के लिए की जाए।

ग्राम पंचायत करोहन के सरपंच से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकोशी यात्रा मार्ग में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को पंचकोशी राशि दिलवाई जाए। मुख्यमंत्री ने वीसी में कहा की सभी पटवारियों को याद रहना चाहिए कि उनके पटवारी हल्के की ग्राम पंचायतों में बंजर भूमि, रकबे की जमीन, आबादी की जमीन कितनी है? उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय जमीन का रिकॉर्ड निकाला जाए तथा वहां भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या विकास के कार्य किया जा सकते हैं इस पर परियोजनाएं बनाई जाएं। सभी ग्राम पंचायतों में बेरोजगार पुरुष और महिलाओं की सूची बनाई जाए। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, वहां पर थानों की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी अप-टू-डेट रखी जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्नत किसानो की जानकारी, महिला पुरुष की शिक्षा, रोजगार संबंधि, मेरिट मे आये बच्चो की जानकारी, अस्पताल, स्कूल, जमीन का रकबा, फसलों के सम्बंधी भी जानकारी भी अपडेट रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने वीसी में निर्देश दिए की ग्राम पंचायतों में सामूहिक विवाह के आयोजन कराए जाएं। आगामी वसंत पंचमी पर भव्य स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाए। लोगों को जागरूक किया जाए कि वे शादी और मृत्यु भोज पर अनावश्यक रुपया बर्बाद ना करें, बल्कि इनका उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में करें ।मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम पंचायत पंथपिपलाई, खेमासा के सरपंचों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई समस्या स्थानीय नागरिकों को नहीं आनी चाहिए। वीसी में जानकारी दी गई की असलाना ग्राम पंचायत में बिजली के तार टूट रहे हैं ,इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत इनकी मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशासनिक संकुल भवन में 1 वर्ष की उपलब्धि पर आधारित जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शनी की प्रशंसा की।

## जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को राहत

### इन 28 ट्रेनों में अब 2 की बजाय होंगे 4 जनरल कोच

**भोपाल (नप्र)।** जनरल कोच में यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने मध्य प्रदेश के स्टेशनों से चलने व गुजरने वाली 28 ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में इजाफा किया है। इन 28 ट्रेनों में अब 2 की बजाय 4 जनरल कोच होंगे। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता नवल अग्रवाल ने बताया कि सामान्य कोच

में सफर करने वाले रेल यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्री यूटीएस एप से अपने टिकट भी बुक कर सकते हैं।

## सीएम के ओएसडी और सुशासन स्कूल के सीईओ ने घरेलू वजह से दिया इस्तीफा

**भोपाल (नप्र)।** अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के प्रभारी सीईओ और मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने 31 दिसम्बर तक का नोटिस मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है। शर्मा के इस्तीफे के बाद अब इस संस्थान के उपाध्यक्ष और नए सीईओ का पद भरा जाएगा। पिछले साल संस्थान के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस्तीफा दे दिया था। तब से इस पद पर किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।

सुशासन स्कूल के प्रभारी सीईओ को राज्य शासन ने सीएम के ओएसडी के साथ सुशासन स्कूल में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इसके बाद फरवरी 2024 में आईएएस अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह को हटाए जाने के बाद से यहां सीईओ की पोस्टिंग नहीं हुई तो शर्मा के पास सीईओ का भी अतिरिक्त प्रभार था।

शर्मा ने कहा कि वे पिछले तीन माह से यहां की सेवा से मुक्त होना चाह रहे थे। इसकी वजह पारिवारिक है। परिवार के सदस्य दिल्ली में रहते हैं। इसकी सहमति मिलने के बाद अब इस्तीफा दे दिया है और 31 दिसम्बर तक नोटिस पीरियड की सेवाएं देंगे। शर्मा ने अपने कार्यकाल में विवादों को लेकर कहा कि कभी किसी तरह का विवाद नहीं रहा है। सरकार की मंशा के मुताबिक काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की वजह निजी है, भले ही उसे कोई अन्य रूप में बताया जाए।

## भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाह के कार्यालय का सामान बाहर फेंका

**भोपाल (नप्र)।** नारायण सिंह कुशवाह 50 -60 समर्थकों के साथ पहुंचे । कार्यालय का सामान भी तोड़ा गया। यह मामला टीटी नगर थाना क्षेत्र का है, कुशवाह भवन को 2026 तक किराए से लिया था। यह भवन सेकंड स्टॉप स्थित अंजली कॉम्प्लेक्स के पास बना है। कुशवाह भवन में बने ऑफिस में की तोड़फोड़ की गई। योगेश मानसिंह कुशवाह के कहने पर एकत्रित हुए थे लोग।

## योग मनोयोग से होता है, सहयोग से नहीं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

### योग मार्ग पर सब चले, योग हमारे जीवन की बदलता है दिशा

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को प्रातः उज्जैन में योग ऋषि स्वामी रामदेव बाबा के शिष्य डॉ. स्वामी परमार्थ देव महाराज के सानिध्य में होमगार्ड मैदान में निशुल्क (इंटीग्रेटेड) योग शिविर में शामिल होकर योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योग मनोयोग से होता है, सहयोग से नहीं। योग मार्ग पर सब चले। योग हमारे जीवन की दिशा बदलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फ्रीगंज का नवीन ब्रिज 21 मी. चौड़ा बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योग करने के बाद संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन निवासी बड़े भाग्यशाली हैं, जो भगवान श्रीमहाकाल, भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली में निवास करते हैं। उन्होने कहा कि परमात्मा ने हमें जो मनुष्य देह दी है उसे सम्भालना अवश्यक है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही योग का बड़ा महत्व रहा है। श्री रामदेव बाबा ने योग को हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने कहा कि 21 जून को योग दिवस और 21 दिसम्बर को ध्यान दिवस मनाया जायेगा, दोनों तिथियां उत्तरायण एवं दक्षिणायान के लिए महत्व रखती है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भौतिकवाद के साथ-साथ प्राचीन विरासत को सम्हालते हुए देश का निरंतर विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। प्रदेश के विकास के साथ-साथ उज्जैन का भी निरंतर विकास जारी है। योग, कुविचार एवं कुरीतियों को खत्म करता है। विधाता ने जन्म दिया है तो सबकी मृत्यु का समय भी नियत किया है, इसलिए हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन को एक के बाद एक नई नई सौगाते मिल रहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ-2028 को देखते हुए होमगार्ड के लिए नवीन जगह उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

## बढ़ते अपराधों से अराजकता का माहौल, कांग्रेस ने आरोप लगाया

### नल-जल योजना के भ्रष्टाचार से बनेगा भाजपा कार्यालय

**(श्याम त्रिवेदी)**

**झाबुआ।** भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करने और सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विधानसभा घेराव आगामी 16 दिसम्बर को राजधानी भोपाल में व्यापक स्तर पर रखा गया है। जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता पर विभिन्न तरह के टैक्सों के माध्यम से आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। बढ़ते अपराधों से प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज की कालाबाजारी की जा रही है। किसानों द्वारा आवाज उठाने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराध से प्रदेश की बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं है। लाखों की संख्या में नौकरी देने का वादा करने वाली

तत्कालीन शिवराज सरकार और वर्तमान मोहन यादव सरकार मे पिछले चार साल मे एक भी सरकारी नौकरी किसी भी युवा को नहीं मिली है।

विधायक डॉ विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा के बड़े नेता यहां आए और यहां आकर उन्होंने किसी गरीब के आंसू नहीं पोंछे वो चार करोड़ का बीजेपी कार्यालय बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये चार करोड भ्रष्टाचार की भेंट चढी नल-जल योजना से आएंगे। नल-जल योजना से बनाई गई पानी की टंकियों मे पानी नहीं आता। टंकियों के बहाने पीएचई विभाग हैंडपंप भी नहीं खोद रहा है। भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित जमीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर भाजपा के कार्यालय को बनाने की बात की जा रही है वो उद्योग विभाग की थी। विधायक डॉ भूरिया ने कहा कि आप चार करोड के बीजेपी कार्यालय की बात कर रहे है और हकीकत यह है कि अतिथि शिक्षकों को उनकी पगार नहीं मिल पा रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों को महिनों से पगार नहीं मिल पा रही है। मप्र की सरकार पर चार लाख करोड़ का कर्ज है। इसे कौन भरेगा।

**मोहन सरकार के एक साल पर विशेष**

# मध्यप्रदेश का लक्ष्य: सशक्त स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण

**राजेन्द्र शुक्ल**

*लेखक मध्यप्रदेश उप मुख्यमंत्री हैं*

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी उद्देश्य के तहत मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य का उद्देश्य है कि न केवल नागरिकों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाए, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत और सक्रिय बनाया जाए। यह दृष्टिकोण केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को बीमारी से पहले ही रोकथाम के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

**स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुगम और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना-** मध्यप्रदेश सरकार सभी नागरिकों तक सुलभ और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक के लिए न केवल सुलभ हों, बल्कि किफायती भी हों, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इसके तहत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को जिला अस्पतालों के समकक्ष सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटी बीमारियों के लिए जिला या बड़े अस्पतालों में जाने की आवश्यकता न हो। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने ही इलाके में इलाज मिल सकेगा, बल्कि जिला अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा।

सक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन में सुधार और बेहतर प्रबंधन के प्रयास किये जा रहे हैं। आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 162 गहन चिकित्सा इकाइयाँ (ICUs) संचालित हो रही हैं, जिनमें 1,584 ICU बेड और 1,003 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। यह सुविधाएं गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ICU और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की संख्या में वृद्धि की जाए और आवश्यकतानुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

**आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों का विस्तार-** मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। इसके तहत सीटी स्कैन और डायलिसिस जैसी विशेष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। CHC स्तर के ऊपर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी (CR) प्रणाली की सुविधा दी जा रही है ताकि सटीक और समय पर निदान संभव हो सके। इसके अलावा, चुने गए जिला अस्पतालों में MRI, इकोकार्डियोग्राफी, और लैप्रोस्कोपिक सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में LINAC, CT, MRI और PET CT स्कैन सेवाओं की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे गंभीर बीमारियों का उन्नत उपचार संभव हो सकेगा। इसके अलावा, कैंसर जैसे गंभीर रोगों के लिए 42 एंटी-कैंसर दवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मरीजों को सही समय पर दवा मिल सके।

**चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता** - मध्यप्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण नागरिकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में असुविधा होती है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है और उन्हें आकर्षक वेतनमान, बेहतर कार्य सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि वे सरकारी सेवा में आकर अपना योगदान दें। साथ ही, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर तैयार हो सकें।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार चिकित्सकों को समय-समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि के माध्यम से भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में 1,607 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और सितंबर 2024 तक 1,902 बॉन्ड डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं और इससे राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

**मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार-** मध्यप्रदेश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। राज्य की मातृ मृत्यु दर (MMR) 173 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसे कम करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सतत विकास लक्ष्यों (SDG) 2030 को प्राप्त करने के उद्देश्य से IPHS 2022 मानकों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधनों का उन्नयन किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकीकृत किया है ताकि बेहतर समन्वय और प्रबंधन हो सके।

महिलाओं की गर्भावस्था और शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 62 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (SNCU) स्थापित की हैं, जहां गंभीर रूप से बीमार नवजातों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा, 199 नवजात

स्थिरीकरण इकाइयाँ (NBSU) भी स्थापित की गई हैं, जो मातृत्व वार्ड के निकट स्थित हैं ताकि बीमार और कम वजन वाले नवजातों का बेहतर देखभाल किया जा सके। शिशुओं के इलाज के लिए राज्य भर में 64 बाल गहन चिकित्सा इकाइयाँ (PICU) भी स्थापित की गई हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का समय से चिन्हांकन कर बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।

**आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में लाया है क्रांतिकारी बदलाव** - आयुष्मान भारत योजना के तहत, मध्यप्रदेश में अब तक 22.22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आयुष्मान कार्ड जारी करने में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में, राज्य के 1,048 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सूचीबद्ध हैं, जिनमें 493 सार्वजनिक अस्पताल और 555 निजी अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत 1,952 स्वास्थ्य लाभ पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, उच्च जोखिम गर्भावस्था, किडनी की बीमारियों और अन्य महंगे उपचार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का प्रावधान किया है। यह वरिष्ठ नागरिकों के देश के विकास में योगदान का सम्मान है। वृद्धजन सहित सभी नागरिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सके और उनका सही उपचार हो सके। नियमित चिकित्सा जांच करवाना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सकीय जांच सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्तमान में, जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 80 प्रकार की जांचें की जा रही हैं। प्रदेश में 324 हब और 1610 स्पोक स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 35,000 से अधिक जांचें जिला स्तर पर और 32,000 से अधिक जांचें हब और स्पोक पर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस, सीटी स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे रोगियों को समय पर और निःशुल्क जांच की सुविधाएं मिल रही हैं।

इसके साथ ही, निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जिला अस्पतालों में दवाओं की संख्या 295 से बढ़ाकर 530 की गई है, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

**प्रधानमंत्री ग्लोबल मेडिसिटी योजना और चिकित्सा पर्यटन का विकास-** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ग्लोबल मेडिसिटी योजना के तहत मध्यप्रदेश में मेडिकल हब का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह हब राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित किए जाएंगे और चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से राज्य को एक वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इन मेडिसिटी हब में अत्याधुनिक सुपरस्पेशलिटी और मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, आयुष चिकित्सा सेवाएं, OPD और डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

**मेडिकल कॉलेजों का विस्तार-** राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं और तीन नए मेडिकल कॉलेजों (सिवनी, नीमच और मंदसौर) को वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए गये हैं। इसके अलावा, आठ अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं जो अगले तीन वर्षों में स्थापित किए जाएंगे।

सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत भी 12 अंडर-सर्व्ड जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना बनाई है। इसके तहत जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मॉडल के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दूरदराज के और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहती है, जिससे वहां की आबादी को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।

इन सभी प्रयासों के माध्यम से, मध्यप्रदेश न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों और राज्य को एक मजबूत और स्वस्थ समाज की दिशा में अग्रसर किया जा जा सके।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश में स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। सरकार के इन प्रयासों से न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और उनकी जीवनशैली में सुधार हो।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश सरकार निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजनाएं न केवल राज्य की जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। इन प्रयासों के साथ, सरकार का लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश न केवल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बने, बल्कि एक सशक्त और स्वस्थ समाज की स्थापना कर देश की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।